

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6 >> फोटोग्राफी की इन शाखाओं में...

भारत ने जूडो में जीता कांस्य

कपिल परमार ने रचा इतिहास, भारत के पदकों की संख्या 25 पहुंची

पेरिस। भारत के पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। कपिल ने पुरुष 60 किग्रा जे। स्पार्थ के कांस्य पदक मुकाबले में ब्राजील के एलिएल्टन डि ओलिवेरा को 10-0 से हराया और कांस्य लाने में सफल रहे। कपिल ने इसके साथ ही इतिहास रच दिया क्योंकि वह भारत के पहले जूडोका हैं जिन्होंने पैरालंपिक या ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया है। भारत ने इस तरह पेरिस पैरालंपिक में अपने पदकों की संख्या 25 पहुंचा दी है। भारत अब तक पेरिस खेलों में पांच स्वर्ण, नौ रजत और 11 कांस्य पदक अपने नाम कर चुका है।

परमार ने 2022 एशियाई खेलों में इसी वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वेनेजुएला के मार्को डेनिस ब्लांको को 10-0 से शिकस्त दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान के एस बनिताबा खोर्रम अब्बादी से पराजित हो गए। परमार को दोनों



मुकाबलों में एक एक पीला कार्ड मिला। कपिल भले ही स्वर्ण नहीं ला सके, लेकिन कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। पैरा जूडो में जे। वर्ग में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं या फिर उनकी कम दृष्टि होती है। भारतीय पैरालंपिक समिति ने इन खेलों से पहले कम से कम 25 पदक जीतने की उम्मीद जताई थी और यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। इससे यहां पैरा खिलाड़ियों का

प्रदर्शन उम्मीदों से अधिक रहेगा। परमार मध्य प्रदेश के शिवोर नाम के एक छोटे से गांव से हैं। बचपन में परमार के साथ एक दुर्घटना हुई थी। जब वह अपने गांव के खेतों में खेल रहे थे और गलती से पानी के पंप को छू लिया जिससे उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा। बेहोश परमार को अस्पताल ले जाया गया और वह छह महीने तक कोमा में रहे। वह चार भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे हैं। परमार के पिता टैक्सि चालक हैं जबकि उनकी बहन एक प्राथमिक विद्यालय चलाती हैं। इस असफलता के बावजूद परमार ने जूडो के प्रति अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मेंटोर और कोच भगवान दास और मनोज को बदलते जूडो में अपने जुनून को आगे बढ़ाना जारी रखा। परमार जख्मों को पूरा करने के लिए अपने भाई ललित के साथ मिलकर एक चाय की दुकान चलाते। ललित उनकी प्रेरणा का स्रोत हैं और आज भी उनकी वित्तीय सहायता का मुख्य स्रोत हैं।

मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे: मोहन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात को कहा कि संघर्ष-ग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति और सुरक्षा की किसी भी गारंटी के अभाव के बावजूद संगठन के स्वयंसेवक मणिपुर में मजबूती से तैनात हैं। वे शंकर दिनकर काणे (जिन्हें भैयाजी के नाम से भी जाना जाता है) को शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिन्होंने मणिपुर में काम किया, 1971 तक बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, छात्रों को महाराष्ट्र लाए और उनके रहने की व्यवस्था की।

मणिपुर में मौजूदा स्थिति कठिन है- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा, मणिपुर में मौजूदा स्थिति कठिन है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर संशयित हैं। जो लोग वहां व्यवसाय या सामाजिक कार्य के लिए गए हैं, उनके लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी संघ के स्वयंसेवक



मजबूती से तैनात हैं, दोनों गुटों की सेवा कर रहे हैं और स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।

एनजीओ सब कुछ नहीं संभाल सकते- भागवत

आरएसएस प्रमुख ने कहा, एनजीओ सब कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन संघ अपनी ओर से हरसंभव प्रयास कर रहा है। वे संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। नतीजतन, उन्होंने लोगों का विश्वास हासिल किया है। इस विश्वास के पीछे का कारण यह है कि स्थानीय लोगों ने वर्षों से इनके जैसे लोगों के काम को देखा है।

इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा, हम

सभी भारत को वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने वाला देश बनाने की बात करते हैं, लेकिन यह केवल केन जैसे लोगों की %लतपस्या% (समर्पण) के कारण ही संभव है। मणिपुर जैसे राज्यों में आज हम जो अशांति देख रहे हैं, वह कुछ लोगों का काम है जो प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन उनकी योजना सफल नहीं होगी।

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जब स्थिति बदतर थी, लगभग 40 साल पहले, लोग वहीं रहे, काम किया और स्थिति को बदलने में मदद की। उन्होंने कहा, संघ के सदस्य, चाहे वे स्वयंसेवक हों या प्रचारक, वहां गए, क्षेत्र का हिस्सा बन गए और बदलाव लाने के लिए काम किया। भागवत ने कहा कि भारत के जिस सपने का सपना देखा गया है, उसे हासिल करने में दो और पीढ़ियां लगेंगी। उन्होंने कहा, रास्ते में, हमें उन लोगों से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जो भारत के उत्थान से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन हमें इन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

सेना की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,

सशस्त्र बलों को रहना चाहिए युद्ध के लिए तैयार

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व बैठक के दूसरे और अंतिम दिन लखनऊ में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन में बोलते हुए, सिंह ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और %आत्मनिर्भर भारत% के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

सम्मेलन की थीम, %सशक्त और सुरक्षित भारत- सशस्त्र बलों में बदलाव% के अनुरूप, सिंह ने संयुक्त सैन्य दृष्टि विकसित करने और भविष्य

में होने वाले युद्धों में देश के सामने का जिक्र करते हुए, मंत्री ने कमांडरों



नेतृत्व द्वारा व्यापक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, भारत एक दुर्लभ शांति लाभ का आनंद ले रहा है और यह शांति से विकास कर रहा है। हालांकि, चुनौतियों की बढ़ती संख्या के कारण, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अमृत काल के दौरान अपनी शांति बरकरार रखें। वहीं इसकी आवश्यकता है हमारे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, वर्तमान में हमारे आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखें और भविष्योन्मुखी होने पर ध्यान केंद्रित करें, इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा घटक होना चाहिए।

से इन प्रकरणों का विश्लेषण करने, भविष्य में देश के सामने आने वाली समस्याओं की भविष्यवाणी करने और अग्रप्रवृत्ति से निपटने के लिए तैयार रहना का आह्वान किया। उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थिति और पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं के मद्देनजर शीर्ष सैन्य

नेतृत्व द्वारा व्यापक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, भारत एक दुर्लभ शांति लाभ का आनंद ले रहा है और यह शांति से विकास कर रहा है। हालांकि, चुनौतियों की बढ़ती संख्या के कारण, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अमृत काल के दौरान अपनी शांति बरकरार रखें। वहीं इसकी आवश्यकता है हमारे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, वर्तमान में हमारे आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखें और भविष्योन्मुखी होने पर ध्यान केंद्रित करें, इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा घटक होना चाहिए।

निवेश के लिए छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ राज्य : देवांगन

छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में उद्योग समागम में की भागीदारी

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम सम्मेलन में भाग लिया। यह कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्यों के उद्योग मंत्री और प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगपतियों, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया, जिसमें व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री देवांगन ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में निवेश की विशाल संभावनाओं और राज्य सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए बेहतर नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों को

प्रोत्साहित करने के लिए कई विशेष योजनाएं और सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे न केवल राज्य का आर्थिक विकास होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। देवांगन ने कहा छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल के रूप में उभर रहा है। प्रदेश खनिज उत्पादन वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है। यहां उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल है। प्रदेश में नए उद्योगों को सर्वसुविधा उपलब्ध कराने के नई रणनीति बनाई गई है।

उन्होंने कहा राज्य में निवेश बढ़ाने व उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन व छूट भी दी जा रही है। देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लांचिंग किया गया है, इससे नए उद्योग शुरू करने वाले व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा 1 नवंबर 2024 से प्रदेश की नई उद्योग नीति भी लागू हो जाएगी। नई नीति उद्यमियों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है।

सांगली में राहुल के कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे ने बनाई दूरी

सांगली। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के सांगली जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संबोधित सार्वजनिक बैठक में शामिल नहीं हुए, जहां राहुल ने महाराष्ट्र के दिवंगत मंत्री परतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर हैं। खबरों के मुताबिक, ठाकरे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाए, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस उनके साथ एकमत नहीं हैं, जिसे इस कार्यक्रम में शामिल न होने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। हालांकि, स्थिति साफ करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी प्रमुख नाराज नहीं हैं और दूर रहने के उनके फैसले के पीछे कोई राजनीति नहीं है। राउत ने कहा कि उनके कार्यक्रम और बैठकें पहले से निर्धारित थीं, और इसलिए वह बाकी समारोह के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस बीच, उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति स्पष्ट रही और इस अवसर पर शिव सेना (यूबीटी) का कोई अन्य नेता मौजूद नहीं था।

भाजपा विस चुनाव के बाद झारखंड से हमेशा के लिए बाहर हो जायेगी

गुमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए उस पर अन्य दलों के विधायकों और सांसदों की "खरीद-फरोख" करने का आरोप लगाया। सोरेन ने दावा किया कि इस साल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्य से हमेशा के लिए बाहर हो जायेगी। उन्होंने आरोप लगाया, "यदि लोग उन्हें (भाजपा) नकार भी दें तो भी वे विधायकों, सांसदों को अपने पाले में कर लेते हैं और सरकार बनाने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं या उन्हें जेल में डाल देते हैं।" मुख्यमंत्री यहां 'आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुमला और लोहरदगा जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सोरेन ने कहा, "जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही हमारा विपक्ष (भाजपा) भी सत्ता के बिना ऐसा ही महसूस करता है।

लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में एनआईए का कदम

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत में आरोप पत्र दायर करते हुए एनआईए ने मुख्य आरोपी ब्रिटेन के हाउरुलो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा पर आरोप लगाए हैं। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि गाबा ने 22 मार्च 2023 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 25 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि इंद्रपाल सिंह गाबा समेत कई संदिग्धों के खिलाफ एलओसी जारी किया गया था। गाबा को पिछले साल नौ दिसंबर को अटारी सीमा पर हिरासत में लिया गया, जब वह पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर रहा था। तब उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था और जांच की गई। एनआईए ने कहा कि गाबा के खिलाफ जांच शुरू की गई और जांच जारी रहने तक उन्हें देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। मामले में एनआईए की अगुवाई में जांच से पता चला है कि पिछले साल 19 और 22 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं भारतीय मिशन में आरोपित अधिकारियों पर हमला करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने लंदन में भारतीय मिशन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी।

मैंने तभी कहा था, ये कांग्रेस की साजिश है: बृजभूषण

नई दिल्ली। भारतीय महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बात की है। गोंडा ने कहा कि जब मुझ पर आरोप लगे तो मैंने कहा कि ये कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश है। ये मैंने पहले भी कहा है और आज देश कह रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मुझे इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता पहले भी कांग्रेस और उसके नेताओं पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं। उस समय बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी दावा किया था कि उनके पास इसे साबित करने के लिए ऑडियो क्लिप हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब माना जा रहा है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में उतर सकते हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है।

विवादित ढांचे को गिराने की मांग, दो दिन का अल्टीमेटम

शिमला। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर संगठनों ने संजौली बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संजौली चौक से ढली टनल और यहां से वापस संजौली चौक पर लोगों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के कारण दोपहर करीब डेढ़ घंटे वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर में बड़ी संख्या में लोग संजौली चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद बाजार में विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस ने धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया था। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए ढली टनल की ओर रवाना हुए। इसके बाद दोबारा संजौली चौक पर पहुंचे। संजौली चौक लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर दो दिनों में अवैध निर्माण नहीं तोड़ा तो वे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर दोबारा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों में आक्रोश इस बात का था कि प्रशासन की आंखों के सामने सातों से अवैध निर्माण होता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हरियाणा में यूपी के दलों की दावेदारी: सत्ता या सिर्फ वोट कटवा

अजय कुमार

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की सियासत के प्रभावशाली दल अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी जैसी प्रमुख पार्टियां हरियाणा की सियासत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन दलों ने अपनी चुनावी रणनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों पर आधारित बनाई है। जहां बसपा और आजाद समाज पार्टी दलित वोटों को अपना आधार मानकर चुनावी मैदान में उतरी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी यादव-मुस्लिम समीकरण का फायदा उठाने की योजना बना रही है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोकदल जाट समुदाय के आधार पर हरियाणा में अपनी पहचान को विस्तार देने का प्रयास कर रहा है। इस स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये उत्तर

प्रदेश के क्षेत्रीय दल हरियाणा की सियासत में प्रभावी हो पाते हैं या सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने भी यही स्थिति दर्शाई थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा संघर्ष होने के कारण हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की स्थिति सियासी हाशिए पर चली गई है। इनेलो और जेजेपी जैसे दलों की सियासी उपस्थिति में काफी कमी आई है। इस परिदृश्य में इन दलों ने दलित आधार वाले दलों के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, यह देखने योग्य होगा।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में चार बार पहुंचकर अपने प्रभाव का प्रदर्शन किया है, लेकिन हरियाणा में उसकी स्थिति हमेशा कमजोर रही है। इस बार मायावती ने

हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया है। इसी तरह, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने दुर्घत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है।

हरियाणा में बसपा और इनेलो ने जाट-दलित समीकरण को ध्यान में रखकर गठबंधन किया है। इस समझौते के तहत बसपा 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर इनेलो अपने प्रत्याशी उतारेगी। 2019 के चुनाव में बसपा हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन उसने 4.21 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे। इनेलो ने पिछले चुनाव में 2.44 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा 24 प्रतिशत था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को 1.74 प्रतिशत



और बसपा को 1.28 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा की कमान युवा नेता आकाश आनंद के हाथ में है, और पार्टी अनुसूचित जाति के 21 प्रतिशत मतदाताओं के सहारे हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। बसपा ने 34 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, जिसमें उसकी सफलता की चुनौती बनी हुई है। 2024 के चुनाव में जाट और दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर दिखा है, जिससे बसपा के लिए हरियाणा में अपनी स्थिति स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। अगर बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता रहा, तो

पार्टी कहीं वोट कटवा पार्टी न बन जाए, यह चिंता बनी रहती है।

चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करने के लिए हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया है। जेजेपी, जो इनेलो से टूटकर बनी है, ने 2019 में हरियाणा की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में उसे अपने सियासी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। चंद्रशेखर ने जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हरियाणा की 90 सीटों में से जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन से जेजेपी को अधिक लाभ की उम्मीद है। चंद्रशेखर ने यूपी में दलितों के बीच अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हरियाणा में उनकी लोकप्रियता सीमित है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और उदयभान जैसे दलित चेहरे राज्य में प्रभावी रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के लिए जेजेपी के साथ

मिलकर हरियाणा में सफलता प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है।

समाजवादी पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की है। अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन अभी तक दोनों दलों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

सपा ने यह भी तय किया है कि अगर कांग्रेस उसे सीट नहीं देती है, तो वह अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां वह चार सीटों पर लड़ी थी और सभी की जमानतें जब्त हो गई थीं।

छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर, दो जवान गंभीर

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। दो दिन पहले हुए मुठभेड़ में जवानों ने 9 नक्सलियों को ढेर किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के बाद अब तेलंगाना पुलिस ने एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर बॉर्डर से लगे तेलंगाना के गुंडाला करकागुडम के नीलाद्रि वन क्षेत्र के झाड़ुगुट्टा गांव के पास ग्रेहाउंड्स फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ में ग्रेहाउंड फोर्स ने 6 नक्सलियों को ढेर किया है, जिसमें दो महिला नक्सली भी शामिल हैं। वहीं कुछ नक्सली घायल हुए हैं। मुठभेड़ में दो जवानों को भी गोली लगी है। घायल जवानों का इलाज जारी है। जवानों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में भद्राद्री कोठागुडम-अह्मरी सीतारामगञ्ज डिविजनल कमेटी (बीकेएसआर डीवीसी) के 6 सीपीआइ (माओवादी) कैडर मारे गए हैं। गुरुवार सुबह करीब 06.45 बजे भद्राद्री-कोठागुडम जिले के करकागुडम पुलिस स्टेशन से 5 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित मोटे गांव के वन क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान पुलिस पार्टी और



नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। वहीं जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू की। जिसके बाद नक्सलियों की ओर से गोलीबारी बंद होने के बाद जवानों ने इलाके की तलाशी ली। इस दौरान घटनास्थल से जैतून हरे रंग के कपड़े पहने 6 शव बरामद किये गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस ने मौके से 2 एके-47, एक एसएलआर, एक 303 राइफल, एक पिस्तौल और मैगजीन, जिंदा राउंड, किट बैग और अन्य सामग्री बरामद किया है। इस मुठभेड़ में ग्रेहाउंड्स के दो जवान घायल हो गए हैं।

घायल जवानों का इलाज तेलंगाना के मुलगा जिला अस्पताल में चल रहा है।

कुछ दिन पहले बीजापुर में नौ नक्सली हुए थे ढेर

वहीं बीती चार सितंबर को छत्तीसगढ़ के देतवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। भारी संख्या में हथियार और मारे गए नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। मुठभेड़ में जवानों ने नौ नक्सलियों को ढेर कर दिया था। पश्चिम बस्तर डिविजन में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। तीन सितंबर को सुबह सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों से हुआ तभी गोलीबारी के दौरान नौ माओवादी मारे गए।

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने नक्सलियों से अपील की थी कि को मुख्यधारा में शामिल हो जाएं नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहें। इसके बाद से ही जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वह छत्तीसगढ़ में मानसून सीजन में भी जमकर सर्च अभियान चला रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड व बीएड संघ ने निकाली रैली

■ 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की मांग, सौंपा ज्ञापन

कबीरधाम, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड व बीएड संघ ने कवर्धा शहर में गुरुवार को रैली निकाली। रैली के माध्यम से संघ ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। यह रैली दोपहर एक बजे निकाली थी। वहीं 1.30 बजे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। रैली में करीब 200 से अधिक लोग शामिल हुए। भीड़ को देखते हुए इन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर गेट पर रोका गया। मौके पर ही जिला प्रशासन के अधिकारी ने ज्ञापन लिया है।

ज्ञापन देने पहुंचे जितेंद्र भास्कर, महेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदेश भर के स्कूल में शिक्षक के हजारों पद रिक्त हैं। भर्ती के लिए लाखों डीएड व बीएड प्रशिक्षित युवा लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेशभर में 57 हजार शिक्षकों की भर्ती किए जाने का वादा किया था। इस पर भरोसा करते हुए सभी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बड़ी संख्या में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, जिसकी बदौलत प्रदेश में भाजपा की सरकार बन सकी है।

इसके अलावा विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन, आज तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं



किए जाने से प्रशिक्षित डीएड व बीएड अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 15 सितंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर संघ द्वारा 21 सितंबर से रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन व अनशन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

ये हैं संघ की प्रमुख मांग

1. प्रदेश के स्कूलों में रिक्त 33 हजार शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ किया जाए, जिसमें सभी संकाय व विषय के पद शामिल हो। शिक्षक वर्ग-2 को भर्ती विषयवार हो। 2. युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला निरस्त किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के 2008 के सेटअप को यथावत रखकर नई भर्ती की कार्रवाई शुरू किया जाए। 3. आगामी शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। प्रदेश के स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में पीजी डिप्लोमा धारियों के लिए पद सृजित कर उनके पदों पर भर्ती की जाए। 4. समय पर भर्ती नहीं होने से कई अभ्यर्थी की उम्र निकल गई है। ऐसे में वह शिक्षक बनने के

लिए अपात्र हो जाएंगे। उन्हें उम्र में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाए।

जांजगीर चांपा में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

जांजगीर चांपा जिले के कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड, डीएड संघ ने 33 हजार शिक्षक भर्ती किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। 15 दिवस का अल्टीमेटम देकर जल्द से जल्द पदों पर भर्ती निकलने की मांग की है नहीं तो उग्र प्रदर्शन की बात स्कूलों की कमी है।

देश भर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर पद रिक्त हैं, जिसकी भर्ती के लिए लाखों बीएड डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी लंबे समय से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो चुनाव समय में अपने घोषणा पत्र में 57 हजार शिक्षक भर्ती किए जाने का उल्लेख किया था, जिसको लेकर लाखों बेरोजगारों ने भाजपा पर भरोसा करते हुए अपना मतदान देकर छत्तीसगढ़ में सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई है। विधानसभा के पहले सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान शिक्षण सत्र में 33 हजार शिक्षकों को भर्ती की घोषणा की थी।

कोरबा में दंतैल हाथी का आतंक सूंड से उठाकर पटका

कोरबा। पाली वन मंडल के धारपखना चुईचुआ सर्किल में दंतैल हाथी ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। पिछले एक माह में हाथी ने चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग के टीम मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली।

बताया जा रहा कि मृतक 60 वर्षीय मेवा राम धनवार रात 10:00 बजे लगभग मुख्य सड़क पर जा रहा था। इस दौरान अचानक हाथी से उसका सामना हो गया और हाथी ने उसे सूंड से उठाकर सड़क पर पटक दिया। जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि हाथी रोड पार कर रहा था। इस दौरान यह घटना घटी और ग्रामीण की नजर हाथी पर नहीं पड़ी। जिसके चलते यह घटना घटी। इस घटना के बाद देखते ही देखते ग्रामीण के



थीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं हाथी ग्रामीण को मौत के घाट उतारने के बाद हाथी गांव की तरफ घुस गया। जहां कुछ लोग घर छोड़कर भागने लगे और किसी दूसरे के घर में सहारा लेकर छुपे हुए थे।

बताया जा रहा है कि मृतक सोनाईपुर का रहने वाला था। वन विभाग की टीम इस घटना के बाद ग्रामीणों को हाथी के पास जाने के लिए मन कर रही थी। वहीं हाथी के पीछे-पीछे वन विभाग की टीम जा रही थी और लाउडस्पीकर के माध्यम से अलाउंस कर रही थी कि गांव में हाथी घुस गया है। घर

से बाहर न निकलें। यह मंजर देर रात तक चलता रहा। जहां हाथी को बिंदरा जंगल की ओर खदेड़ा गया।

बता दें कि कोरबा के कटघोरा वन मंडल में तीन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद जांजगीर के पंतोरा जंगल में डेरा डाला था। जिसके बाद बिलासपुर जंगल में था। दो दिन से कोरबा पाली वन मंडल पहुंचा और फिर से ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और हाथी पिछले एक माह से कोरबा जांजगीर चांपा और बिलासपुर वन मंडल में घूम रहा है। कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आसपास मुनादी गांव में कराई जा रही है।

बस्तर दशहरा मनाने के लिए समिति ने राज्य सरकार को डेढ़ करोड़ का भेजा प्रस्ताव

जगदलपुर। बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि इस वर्ष रियासत कालीन बस्तर दशहरा के परंपराओं निर्वहन के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। डेढ़ करोड़ रुपए में चावल-17 लाख, किराना- 9 लाख, रसूम, बिदाई रसूम - 4 लाख रुपए।

मंदिर व रथ बिजली सजावट, एलईडी- 32 लाख 10 हजार। कुर्सी, शांतिघाना, टेंट व अन्य- 19 लाख 50 हजार। गाड़ी मरम्मत व अन्य गाड़ी किराया 16 हजार 500। डीजल - 8 लाख 20 हजार। लोहा- 38 हजार रुपए। फल, फूल और भोग मिठाई- 4 लाख 81 हजार 500 रुपए। रथ, रस्सी व कपड़ा सिलाई- 3 लाख 60 हजार। रंगाई व पुताई- 6 लाख 8 हजार। कपड़ा 11 लाख 50 हजार। फटाखे - 6 लाख। प्रचार प्रसार व स्टेशनरी सामग्री-3 लाख। रथ लकड़ी के लिए लकड़ी चिराना-2 लाख 80 हजार रुपए और अन्य खर्च 8 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि बस्तर दशहरा महापर्व मनाने के लिए

समिति ने राज्य सरकार को डेढ़ करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। पिछले वर्ष 1 करोड़ 44 लाख 63 हजार 298 रुपए खर्च हुए थे। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस साल दशहरा मनाने में करीब 1 करोड़ 50 लाख 16 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है।

कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तर दशहरा समिति को दसरा पसरा की भी जानकारी देते हुए बताया कि दसरा पसरा में प्रशासन ने आदिवासी जनजातियों के संस्कृति एवं इतिहास के संरक्षण के लिए भवन निर्मित किया गया है। साथ ही संस्कृति और इतिहास के संबंध में ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति दी जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए खुला सभागार, कैफेटेरिया और संचालन समिति हेतु प्रशासनिक भवन के रूप में उपयोग करने की बात कही। बस्तर दशहरा मनाने के लिए हर साल करीब 200 पेड़ काटे जाते हैं। इसके चलते जिला प्रशासन एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम का अभियान चलाया जा रहा है।

25 लाख 44 हजार के पीडीएस खाद्यान्न सामाग्री के हेरा-फेरी करने वाले 2 सेल्समेन गिरफ्तार

सुकमा। जिले के थाना चिंतलनार क्षेत्र के पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न सामाग्री अनुरूपित बाजार मूल्य पच्चीस लाख चौवालीस हजार एक सौ पंचानव रुपये की हेरा-फेरी एवं कालाबाजारी करने वाले 2 सेल्समेन विजय कुमार हेमला एवं भीमसेन वेद्री को थाना चिंतलनार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलमपल्ली एवं केरलापेंदा का संचालन ग्राम चिंतलनार बाजारपार से हो रहा था। उपरोक्त खाद्यान्न सामाग्री पहुंचे विहीन ग्रामों के हितग्राहियों के लिए भण्डारण किये गये, खाद्यान्न को राशन कार्डधारियों को वितरण नहीं कर कालाबाजारी करने के उद्देश्य से अलग-अलग स्थान पर छुपा कर रखा गया था।

थाना चिंतलनार में अपराध क्रमांक 13/24 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 316 भा. न्या. संहिता के प्रकरण में आरोपी सेल्समेन विजय कुमार



हेमला पिता भीमा ग्राम बंजेपल्ली ग्राम पंचायत एलमपल्ली तथा थाना चिंतलनार के ही अपराध क्रमांक 14/24 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 316 भा. न्या. संहिता के आरोपी सेल्समेन भीमसेन वेद्री पिता रामलाल वेद्री ग्राम केरलापेंदा विवेचना के दौरान फरार हो गए थे, जिन्हें पता तलाश के दौरान ग्राम झारपा थाना सुकमा से गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें आज गुरुवार को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय सुकमा पेश किया गया। इस प्रकरण के शेष

आरोपीगण ग्राम पंचायत एलमपल्ली सरपंच श्रीमती हिमानी मड़कम, सचिव गोपी कृष्ण सिंह राजपूत एवं ग्राम पंचायत केरलापेंदा सरपंच श्रीमती तेजाम पायके, सचिव हिमाचल पुरी फरार हैं, जिनका पता-तलाश किया जा रहा है। इस कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी के दिशा-निर्देशन में उप निरीक्षक विमल वेद्री थाना प्रभारी चिंतलनार, सर्जन. मतबल साय पैकरा, प्रधान आरक्षक सोडू हिडुमा, आरक्षक निरज पाण्डेय एवं आरक्षक मोहन मंडावी का योगदान रहा।

अबिकापुर में तेज बारिश कॉलोनिआ बनी स्वीमिंग पूल

सरगुजा। अबिकापुर में बुधवार को पूरे दिन भारी बारिश हुई ये बारिश रात में भी नहीं रुकी। जिसके बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं जिसके कारण लोगों के घरों में पानी भर गया है। अबिकापुर के घुटरापा में आलम ये है कि घरों में इतना पानी भरा है, लोग अपनी गृहस्थी का सामान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वाहन पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अबिकापुर नगर नगम हर बारिश से पहले ड्रेनेज सिस्टम को मंटेन करने की बात करता है, लेकिन बारिश ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया जिससे लोग खासे परेशान हैं। जब भी भारी बारिश होती है शहर का ये इलाका सबसे पहले डूबने में स्थिति में आ जाता है। वार्डवासी शेखर अग्रवाल ने कहा मेरे घर में घुटनों तक पानी भर गया था। करीब रात में 2 बजे तेज बारिश शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे घर में पानी भरना शुरू हुआ। बाइक भी पूरी डूब गई थी, नुकसान तो हुआ ही है, जब भी हैवी बारिश होती है तो यहां ऐसा ही होता है। नगर निगम को ध्यान देना चाहिये।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खैरागढ़ पुलिस का नाम

राजनांदगांव। खैरागढ़ जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने नेतृत्व में समर्थ अभियान चलाया। इस अभियान को शुरू करने का मकसद बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम लगाना है। इस अभियान में मवेशियों को 200 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जिसके बाद खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। खैरागढ़ के डॉ नरेंद्र वर्मा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव रेंज आईजी, संधाग आयुक्त, कलेक्टर, एसपी सहित गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रदेश प्रभारी सोनल शर्मा ने खैरागढ़ एसपी त्रिलोक बंसल को सर्टिफिकेट दिया और साइबर जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम की तारीफ की। राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा ने खैरागढ़ एसपी और पुलिस की तारीफ की। उन्होंने दूसरे जिलों के पुलिस को भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी।

जंगल में बैल चरा रहे सरपंच पर गिरी गाज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ग्राम पंचायत रौनी के सरपंच रामवृक्ष राम को गुरुवार को एक दुखद घटना में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ जंगल में मवेशियों को चराने समय यह दुर्घटना घटी जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई और उन्हें बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब सरपंच रामवृक्ष और उनकी पत्नी सुबह के समय गांव के पास के जंगल में अपने बैल चराने गए थे। अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज बारिश के साथ गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस शक्तिशाली बिजली की चपेट में आने से सरपंच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आईं और वह बुरी तरह से झुलस गई। घटना की जानकारी मिलते ही बगीचा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत ही आवश्यक जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सरकारी राशन में हेराफेरी करने वाले 4 समिति सरपेंड

बिलासपुर। जिले में सरकारी राशन दुकान में 50 लाख के 800 क्विंटल अनाज की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला है कि पीडीएस का चावल बाजार में बेचा जा रहा था। इस मामले में कोटा एसडीएम ने कोंचरा, सोनपुरी, आमामुड़ा, और करी की समितियों को सरपेंड कर दिया है और विस्तृत जांच की जा रही है। कोटा विकासखंड के कोंचरा, सोनपुरी और आमामुड़ा और करी सोसायटी में प्रबंधक और विक्रेताओं ने सरकार को लाखों का चूना तो लगाया ही है, आम गरीब जनता को जो राशन मिलना चाहिए उसमें भी संधमारी की है। लगातार शिकायत के बाद से इन सोसायटियों का भौतिक स्थापन किया गया तो गड़बड़ी पकड़ में आई। जांच के बाद कोंचरा सोसायटी में 317.24 किं. चावल, 8.24 किं. शक्कर और 2.72 किं. नमक की कमी पाई गई। इसी प्रकार सोनपुरी में 200.85 किं. चावल, 3.77 किं. शक्कर, आमामुड़ा सोसायटी में 177.72 किं. चावल, 5.04 किं. शक्कर और करी की आनंद महिला समूह में 91.90 किं. चावल और 0.65 किं. शक्कर की कमी पाई गई थी।

स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई

बिलासपुर। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) से नदारद चार डॉक्टरों को सीएमएचओ ने नोटिस जारी किया है। जांच के दौरान बीते 31 अगस्त को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चार डॉक्टर अनुपस्थित थे। जबकि रतनपुर क्षेत्र में इन दिनों मलेरिया, डायरिया का प्रकोप फैला है। बताया जा रहा है कि मामले की शिकायत आला अधिकारियों तक पहुंच गई है। रतनपुर क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप है। बड़ी संख्या में पीड़ित इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। शिकायत पर जांच करने टीम पहुंची तब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चार डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद थे। सीएमएचओ ने उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला शाहा, डॉ. नेहल झा, नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉ. एम. एल. कोराने, एस्थेथीसिया निधि कोराम शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया है। लोगों को कहना है कि रतनपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला सही तरह से काम नहीं कर रहा।

डबरी से सिंचाई की सुविधा पाकर रामप्यारे के सूखे खेतों में आई हरियाली

■ मनेंद्रगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पिपरिया

एमसीबी। जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पिपरिया की भौगोलिक स्थिति वनांचल जैसी ही है। यहां पानी बरसता तो बहुत है परंतु बह जाता है ऐसे में किसानों के लिए समय पर सिंचाई के लिए पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। वंचित वर्ग में आने वाले ऐसे ही एक आदिवासी परिवार के लिए छेत्री योग्य भूमि होने के बाद भी पानी का संसाधन ना होना एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में मनेंद्रगढ़ के तहत बनी एक डबरी से सिंचाई का साधन उनकी खुशहाली का माध्यम बन गया है। पहले केवल मानसूनी बारिश पर आधारित धान की खेती करने वाले आदिवासी किसान रामप्यारे के खेतों में हर बार कभी रोपाईं में या तो कभी फसल



पकने के समय पानी की कमी हो जाती थी। ऐसे में मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपनी फसल से कोई लाभ नहीं मिल पाता था। परंतु इस बार सिंचाई की सुविधा पाकर रामप्यारे के परिवार ने समय पर अपने खेतों में रोपाईं का कार्य पूरा कर लिया है और उनकी धान की फसल भी लहलहा रही है। इस खुशहाली के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनी

एक डबरी इस किसान परिवार के लिए चरदान साबित हो रही है।

पहले श्री रामप्यारे का परिवार खेती के लिए हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि उनके पास खेत तो थे परंतु सिंचाई का साधन नहीं था। ऐसे में वह परंपरागत खेतों में समय पर धान की रोपाईं का काम नहीं ले पाते थे। उनकी इस समस्या का निराकरण हुआ ग्राम सभा की बैठक में, जहां उन्होंने अपने खेतों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक डबरी बनाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। उनके आवेदन के आधार पर ग्राम सभा ने डबरी बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया और ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाते हुए 2 लाख 95 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत द्वारा गत सितंबर माह से कार्य आरंभ कर इस वर्ष जून में उनके खेतों में एक डबरी का निर्माण कार्य पूर्ण

कराया गया। इसमें अकुशल मजदूरी करके इस परिवार को सौ दिवस का रोजगार भी प्राप्त हुआ। डबरी बन जाने के बाद खुश रामप्यारे बताते हैं कि सब्जी लगाकर वह लगभग 20 हजार रुपए की आमदनी ले चुके हैं और फिर कई वर्षों के बाद उनके परंपरागत खेतों में समय पर धान की रोपाईं का काम पूरा हुआ है। इससे धान की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। डबरी में पर्याप्त पानी होने के कारण वह इसमें अगले साल से मछली पालन भी करने वाले हैं। रामप्यारे के अनुसार लगभग तीन एकड़ खेतों में इस बार अच्छी धान की फसल होने से लगभग एक लाख रूपए का सीधा लाभ मिलेगा। मनेंद्रगढ़ से बना एक संसाधन इस परिवार के लिए आजीविका की नई राह बना रहा है। इसके लिए रामप्यारे ने जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

डीएमएफ के कामों की पहले होगी जांच, फिर होंगे नए काम स्वीकृत : भोजराज नाग

बालोद। लोकसभा चुनाव के बाद जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भोजराज नाग ने सांसद बनने के बाद से अब तक जिले में अफसरों की बैठक नहीं ली है। जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाया जा रहे थे। ये भी बात सामने आई थी कि सांसद ने दो दृढ़ अधिकारियों से कहा है कि पुराने हुए कामों की जांच करी उन्हें चाहिए। तभी आगे बैठक होगी और आगे काम स्वीकृत किए जाएंगे।

बालोद जिले में डीएमएफ की मदद से कई विकास कार्य करवाए गए हैं लेकिन कई बार फंड के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। अच्छे से जांच की जाए तो कई अफसर और जनप्रतिनिधि तक भी इसकी आंच जाएगी। कई नेताओं ने बड़े-बड़े छोटे-छोटे काम किए हैं और यह सभी काम विवादों में रहा है। सांसद भोजराज नाग के स्पष्ट दावों से ये कहा जा सकता है कि पहले हिसाब होगा फिर विकास होगा। उन्होंने कहा है कि जांच हो और दौषियों के



ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।

भोजराज नाग ने कहा जिला खनिज संस्थान न्यास मद हो या फिर चाहे जो कोई भी काम हो जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जांच कराई जाएगी और उन पर कार्रवाई भी कराई जाएगी। आपको बता दें सांसद ने विकास कार्यों के लिए डीएमएफ मद से काम करने को लेकर अफसरों को निर्देशित किया है। इसलिए पिछले 6 महीनों से कोई भी काम इस मद से स्वीकृत नहीं हुए हैं। साथ ही साथ पुराने कामों को लेकर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सांसद ने मांगी है।

आरएसएस को खुश करना चाहती है भाजपा!

हरीश गुप्ता

भले ही यह अजीब लगे, लेकिन सच है। यह सामने आया है कि भाजपा नेतृत्व अपने मातृ संगठन आरएसएस को खुश करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार के दो हालिया फैसलों ने न केवल राजनीतिक पर्यवेक्षकों को बल्कि आरएसएस को भी हैरान कर दिया है। सरकार ने स्वप्रेरणा से लिए गए फैसले में सरकारी कर्मचारियों को दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन आरएसएस में शामिल होने की अनुमति दे दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस ने लगभग 40 साल पहले कांग्रेस शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आग्रह 2015 में सरकार से किया था। आरएसएस ने 2015 के बाद से सरकार को कभी इसकी याद नहीं दिलाई, हालांकि दोनों एक-दूसरे को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। एक और फैसला जो अचानक आया, वह है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करना। आरएसएस प्रमुख ने अपनी सुरक्षा को और बढ़ाने की कोई मांग नहीं की थी। लेकिन खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बराबर सुरक्षा कवर को जेड प्लस स्तर का कर दिया। हालांकि जेपी नन्डू की जगह नए भाजपा प्रमुख की नियुक्ति के सवाल पर आरएसएस नरम पड़ने को तैयार नहीं है। आरएसएस नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगला भाजपा प्रमुख उसके द्वारा सुझाया गया व्यक्ति होना चाहिए। प्रधानमंत्री सरकार के कामकाज को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, यह पूरी तरह से उनका विशेषाधिकार है। लेकिन जब बात भाजपा की आती है, तो उसे अपनी पसंद का व्यक्ति रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। समय की कमी के मुख्य कारण सहित अन्य कारणों से नए भाजपा प्रमुख पर आम सहमति नहीं बन पाई है। इस निर्णय को अगले साल की शुरुआत तक टाल दिया गया है और आरएसएस को उम्मीद है कि 'पारिवारिक मामला' सुलझ जाएगा। जम्मू-कश्मीर सेवा के 2010 बैच के आईएसएस अधिकारी डॉ। शाह फैसल भाग्यशाली रहे कि आईएसएस की नौकरी छोड़ने और एक बार 'परिवर्तन की राजनीति' से जुड़ने के बाद उन्हें फिर से सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। यह एक दुर्लभ मामला था क्योंकि वे सरकार में वापस आ गए। डॉ. शाह ने वीआरएस लिया और एक राजनीतिक पार्टी बनाई, दो साल बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और सेवा में वापस आ गए। इस पर कुछ लोगों की भौंहें तन गईं, लेकिन मोटे तौर पर लोगों ने इसका स्वागत किया। अब एक और आईएसएस अधिकारी को भी यही उम्मीद है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले वीआरएसएस लेकर राजनीति में शामिल होने वाले यूपी कैडर के 2011 बैच के तेजतरंग और मुखर आईएसएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद सेवा में वापस आना मुश्किल लग रहा है। मॉडेल और फिल्म अभिनेता अभिषेक सिंह ने अब केंद्र को आवेदन करके सेवा में वापस लेने का अनुरोध किया है, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें वापस न लेने की सिफारिश की है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। सूत्रों ने बताया कि अभिषेक सिंह की राजनीतिक सक्रियता के कारण भारत सरकार भी उनके नाम पर विचार करने को तैयार नहीं है। सिंह ने अक्टूबर 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जौनपुर से भाजपा से लोकसभा का टिकट हासिल करने के लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुए। जाति जनगणना और आरक्षण के लिए उनके समर्थन ने चीजों को और भी मुश्किल बना दिया है। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल वर्तमान में लखीमपुर खीरी की डीएम हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। जब से कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनावों में 99 लोकसभा सीटें जीती हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से उनके बारे में दुनिया का नजरिया काफी बदल गया है। यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं और भाजपा को जाति जनगणना सहित उनके द्वारा उठाए गए कई मुख्य मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन चौंकाने वाली बात स्मृति ईरानी का पलटवार था, जो दशकों से उनकी धुर विरोधी रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेटी में राहुल गांधी को हराने के बाद, ईरानी सातवें आसमान पर थीं। उन्होंने उनका नाम लेकर मजाक उड़या। लेकिन राहुल गांधी के सहयोगी किशोरी लाल शर्मा द्वारा अमेटी से अपमानजनक हार के बाद, वह अपना मंत्री के नाते मिला बंगला खाली करने के बाद लगभग गायब हो गई। अचानक वह परिदृश्य में आई और राहुल गांधी के नए दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर का जनादेश चौंकाने वाला होगा

नीरज कुमार दुबे

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की ओर से नामांकन दाखिल किये जा रहे हैं। विभिन्न दलों के स्थानीय नेता तो चुनाव प्रचार में उतर ही चुके हैं साथ ही बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता भी चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं। गलियों और मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चल रहा है, रोड शो निकाले जा रहे हैं, घर-घर जाकर नेता लोगों से वोट मांग रहे हैं। जनता भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। यह सब कुछ भयमक वातावरण में हो रहा है जोकि कश्मीर घाटी के लोगों के लिए नई बात है। जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं उन युवाओं ने तो ऐसा माहौल पहले कभी देखा भी नहीं था।

इस बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी खास है कि कश्मीर घाटी में परिवारवादी दलों के दिन अब लड़ते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के हृदय माने जाने वाले लाल चौक का नजारा बता रहा है कि यहां की जनता इस बार चौंकाने वाला जनादेश देने जा रही है। कश्मीर घाटी में एक समय आतंक और अलगाववादियों का राज था लेकिन आज यहाँ विभिन्न चौक-चौराहों पर तिरंगा लहरा रहा है, खासकर लाल चौक पर शान से आसमान को छूता तिरंगा सबका ध्यान आकृष्ट करता है। अब घाटी में पर्यटकों का जमावड़ा बिना किसी खोफ के लगता है। लाल चौक पर जहां पहले शाम के बाद कोई नहीं दिखाई देता था आज वहां देर रात तक चहल पहल रहती है और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को देखकर लोग कश्मीरी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होते हैं।

हम आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता के रूप में जब तिरंगा यात्रा का लाल चौक तक नेतृत्व किया था तब वहां तिरंगा फहराने का मतलब जान से खेलना था लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर ऐसा बदला कि आज लाल चौक का शांत और खुशहाल नजारा पूरे कश्मीर के बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप हाल ही में कभी लाल चौक गये होंगे या श्रीनगर शहर का दौरा किया होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे स्मार्ट सिटी अभियान के तहत इस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया है। कश्मीर घाटी में किये गये विकास के बलवृत्ते भाजपा को उम्मीद है कि यहां की जनता इस बार परिवारवादी दलों की बजाय उसका साथ देगी।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद



370 को हटाये हुए पांच साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान जम्मू-कश्मीर ने वो खुशी देख ली है जो बीते तीन-चार दशकों में उससे छीन ली गयी थी। सिर्फ पांच सालों में आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पाँव पर खड़ा कर देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस कश्मीर घाटी में पहले आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराये जाते थे आज वहां यह सब बंद हो गया है और हर घर पर तिरंगा फहरा रहा है। लाल चौक में तिरंगा फहराने पर पहले गोली लगने का खतरा रहता था लेकिन आज नये रंग रूप में लाल चौक पर शान से फहराता तिरंगा हर किसी को नये कश्मीर का अहसास करा रहा है। यही नहीं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करने वाले हुर्रियत जैसे अलगाववादी संगठन के कार्यालय पर भी तिरंगा लहरा रहा है।

विपक्ष भले आज भी 370 की वकालत कर रहा हो लेकिन देश देख रहा है कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटया तो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद घर रोक लग गयी। पत्थरबाजी पूरी तरह बंद हो गयी, धर्मस्थलों से धार्मिक तकरीरों की बजाय राजनीतिक और भड़काऊ भाषण दिये जाने बंद हो गये, कश्मीरियों के बच्चों को अलगाववादियों की ओर से बहका कर गलत राह पर ले जाना बंद हो गया, आतंकवाद के प्रति लोगों की सोच में ऐसा परिवर्तन आया है कि अब सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की राह में बाधा नहीं पैदा की जाती बल्कि उनकी मदद की जाती है और कई उदाहरण तो ऐसे भी देखने में आये जब ग्रामीणों ने ही आतंकवादियों को दबोच कर उन्हें सुरक्षा बलों को सौंप दिया।

जम्मू-कश्मीर में स्कूल-कॉलेजों का बंद रहना और हड़तालों का आयोजन अब बीती बात हो गयी है, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर रोक लग गयी है, सीमा पार से होने वाली गोलीबारी बंद हो गयी जिससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को जब-तब भाग

कर बंकरों में छिप कर जान बचाने से आजादी मिली। 370 हटने से पुलिस, सेना और अन्य जांच एजेंसियों के बीच ऐसा अच्छा समन्वय बना कि जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था की नाकामी के चलते होने वाली आपराधिक घटनाओं में 97 प्रतिशत की गिरावट आ गयी और आतंकवाद संबंधी घटनाएं पहले से घटकर आधी से भी कम हो गयीं।

यही नहीं, जम्मू-कश्मीर में अब किसी एक परिवार का शासन नहीं चलता बल्कि निचले स्तर तक लोकतंत्र मजबूत हो गया है। पहली बार डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए, पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायती राज तंत्र जम्मू-कश्मीर में कायम हुआ, इसके तहत 33274 जनप्रतिनिधि चुने गये। यही नहीं हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण रहे जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया और उमर अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती जैसे परिवारवादी नेताओं को हार का स्वाद चखा दिया।

पिछले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढांचे का इस तरह विकास किया गया है कि यह केंद्र शासित प्रदेश आज बड़े से बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर सकता है। हाल ही में श्रीनगर में जी-20 देशों की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भी श्रीनगर में ही आयोजित किया गया जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया।

बदलते जम्मू-कश्मीर की नयी तस्वीर को देखेंगे तो पाएंगे कि इस केंद्र शासित प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें हैं। विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज चेनाब में बन रहा है जोकि कश्मीर में है। इस केंद्र शासित प्रदेश में एमएस, आईआईएम और आईआईटी की स्थापना का कार्य चल रहा है। यहां पिछले पांच सालों में सैंकड़ों पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 39 सुरंगों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है जिससे आने वाले दिनों में हर मौसम में जम्मू-कश्मीर में कहीं भी आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर को मिली परियोजनाओं ने यहां की तकदीर और तस्वीर, दोनों बदल कर रख दी है।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में अब केंद्रीय योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को मिल रहा है, भूमिहीनों को सरकार जमीन दे रही है, युवाओं को नौकरी

मिल रही है, स्वरोजगार की चाह रखने वालों को कौशल प्रशिक्षण और कारोबार खड़ा करने के लिए आसानी से कर्ज मिल रहा है, सभी धर्मों के लोग अपने पर्वों को शांतिपूर्वक मना पा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा सफलता के साथ संपन्न हुई, वार्षिक खीर भवानी मेले में भारी भीड़ जुटने लगी है और मुहर्रम का जुलूस निकलने लगा है। इसके अलावा, कश्मीरी पंडितों के सुरक्षा हालात में बड़ा सुधार आया है, उनके लिए रोजगार से लेकर अनावस तक की व्यवस्था की गयी है। आतंकवाद के दौर में तबाह कर दिये गये हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, कश्मीरी महिलाओं को आर्यमर्भर बनाया जा रहा है। कश्मीर में दूरदराज के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हासिल करने के लिए ज़्यादा मशकत नहीं करनी पड़ती क्योंकि प्रशासन खुद उनके पास चलकर जाता है।

देखा जाये तो जम्मू-कश्मीर में इस समय विकास की नयी बहार बह रही है। आप जम्मू या श्रीनगर जैसे बड़े शहरों में चले जाइये या फिर किसी दूरदराज के सीमायी इलाकों में स्थित गांवों में, हर जगह आपको बुनियादी ढांचा परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य होते या सरकारी योजनाओं के लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करते कार्यक्रम आयोजित होते दिख जायेंगे। दूरदराज में कई पहाड़ी इलाके हैं जहां आजादी के बाद से अब तक विकास नहीं पहुंचा था लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हालात में बदलाव आया है। दूरदराज के पंचायत क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की लंबे अरसे से लंबित मांगों को पूरा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल-कॉलेज और अस्पताल तो बन ही रहे हैं साथ ही सड़क संपर्क को भी सुधारा जा रहा है जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। देखा जाये तो कश्मीर के गांवों में रहने वालों को असल आजादी तब मिली जब उन्हें कच्चे घरों से मुक्ति मिली। जम्मू-कश्मीर के तमाम गांवों में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाड) के तहत ग्रामीणों को पक्का घर मिला। आजादी के 75 साल बाद पहली बार सड़क, पुल संपर्क, बिजली का कनेक्शन और पक्के मकान पाकर ग्रामीण खुश

हैं। अब खुद चलकर मूलभूत सुविधाएं दरवाजे पर आ रही हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाओं के विकास और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के आयोजन की वजह से यहां नये नये खिलाड़ी निकल रहे हैं। खेलो इंडिया आयोजन में केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने जोश, उत्साह और प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया।

पुराण दिग्दर्शन

परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-14)

गतांक से आगे...

उपर्युक्त सम्मति का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार देखने में नेत्र ही प्रमाण हैं, और सुनने में कान ही प्रमाण हैं, इसी प्रकार गन्ध में नासिका, स्पर्श में त्वचा, रस में जिह्वा आदि इन्द्रियें भी अपने 2 विषयों में प्रमाण हैं। एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय के विषय का निरूपण नहीं कर सकती। इसी भाँति वेद स्मृति और पुराण भी अपने-अपने विषयों में निरपेक्ष प्रमाण हैं। सो सर्ग प्रतिस्मादि का ऋमबद्ध वर्णन और लोक वृत्तान्त केवल पुराणों का विषय है अतः उक्त विषय में पुराणों की प्रामाण्यता न्याययुक्त है।

हम नहीं समझते कि जो लोग मेवाड़ के यवन कालीन इतिहास के लिये टाड राजस्थान की किताबों और अंग्रेजकालीन इतिहास के लिये ई० मांसडन आदि की किताबों को प्रमाण मानकर तत्कालीन घटनाओं पर विश्वास कर सकते हैं, वे ही महाशय पुराणों की इस आंशिक प्रामाण्यता पर क्यों आपत्ति

करते हैं ? व्याय में पंचावयव वाक्य द्वारा ही प्रत्येक विषय की साधना मानी जाती है। लोक में भी न्यूनातिरिक्त इसी शैली से समस्त निर्णय किये जाते हैं। इस प्रकार भी वेद और स्मृति को पक्ष-ग्रन्थ, दर्शनों को हेतुग्रन्थ और पुराणों को दृष्टान्त्रग्रन्थ कहा जा सकता है। इन तीनों के सम्मेलन से जो निश्चित होगा वास्तव में उसे ही सिद्धान्त कहा जा सकता है। हेतु-विकल या दृष्टान्त-विकल पक्ष को सिद्धान्त मानना युक्तियुक्त नहीं जंचता। इसीलिये यस्तर्कणानुसन्धते इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपनृ ह्येत इत्यादि वचनों द्वारा वेदार्थ-निर्णय में दर्शनों की उपयोगिता प्रकट की गई है।

आलंकारिक प्रक्रिया- अलङ्कार शास्त्र में उपदेश विधायक ग्रन्थों को तीन भागों में बाँटा है (2) प्रभु सम्मित (2) मित्र सम्मित और (3) कान्त सम्मित।

ऋमशः ...



प्रज्ञा पाण्डेय

आज हरियाली तीज है, इस दिन महिलाएं पति के लिए उपवास रखकर शिव-गौरी की पूजा करती है। सुहागन स्त्रियां झुला झूलती हुए सूरिले स्वर में सावन के गीत-मल्हार गाती हैं।

हिंदू धर्म में हरियाली तीज पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का विधान है। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज त्योहार को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस विशेष दिन पर पूजा-पाठ और स्नान-दान करने से विशेष लाभ मिलता है। हरियाली तीज का पवित्र त्योहार इस वर्ष 7 अगस्त



को मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर महिलाएं अपने घर की सुख-समृद्धि के लिए, व्रत रखती हैं।

हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त- पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 06 अगस्त को रात 07 बजकर 52 मिनट पर होगी। वहीं, इसका समापन अगले दिन यानी 07 अगस्त को रात 10 बजकर 05 मिनट पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। अतः 07 अगस्त को

हरियाली तीज मनाई जाएगी।

हरियाली तीज के दिन ऐसे करें पूजा - पंडितों के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ और सुन्दर वस्त्र-आभूषण पहनें। फिर एक स्वच्छ स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर वहां एक चौकी पर माता गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र

स्थापित करें। पूजा विधिपूर्वक शुरू करें, जिसमें सबसे पहले भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर हरे रंग की सजावट करें और हरे पत्ते चढ़ाएं। फल, मिठाई और अन्य भोग अर्पित करें, विशेषकर फल, मेवे, और हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं। पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में, पूजा समाप्त करने के बाद परिवार के साथ प्रसाद वितरित करें। यह पूजा माता गौरी की कृपा प्राप्त करने और

घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए की जाती है।

हरियाली तीज के व्रत के बारे में धार्मिक मान्यता है कि, यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए किया था। अक्सर लोग मानते हैं कि ये व्रत सुगहागिनों के द्वारा ही मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को शिव जी ने सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्वीकार किया था। इस शुभ दिन पर कुवारी लड़कियां मनाचहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं और विवाहित महिलाएं सुख-समृद्धि में वृद्धि के लिए महादेव को पूजा-अर्चना करती हैं। इसलिए हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है।

ब्रुनेई और सिंगापुर की महत्वपूर्ण यात्रा

डॉ. धनंजय त्रिपाठी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रुनेई के बीच चार दशक के कूटनीतिक संबंधों के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा की है। वेसे प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया की पहले मुलाकातें हो चुकी हैं। जैसा कि यात्रा से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है, इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्रुनेई और सिंगापुर दस दक्षिण-पूर्वी देशों के समूह आसियान के सदस्य हैं। कुछ वर्ष पहले आसियान के नेताओं ने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में भारतीय विदेश नीति में पूर्वी एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, हालांकि उस क्षेत्र के साथ हमारे संबंध लंबे समय से अच्छे रहे हैं। 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की नीति का मुख्य कारण है चीन से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। दक्षिण चीन सागर में चीन और उसके कुछ पड़ोसी देशों, जो आसियान के सदस्य हैं, के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, जो अब टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। ब्रुनेई भी सीआउ चान्ग सी क्षेत्र का एक देश है। इस रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

आसियान देशों के साथ संबंध बेहतर करने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र भी भारत के एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस संबंध में भी यह दौरा अहम है। ब्रुनेई उन देशों में है, जिनके साथ



भारत की कभी कोई समस्या नहीं रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से परस्पर विश्वास और सहयोग को ठोस आधार मिलेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। इस यात्रा के दौरान जो मुख्य मुद्दे हैं, वे रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग से संबंधित हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत और ब्रुनेई रक्षा क्षेत्र में एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। ब्रुनेई की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंचे हैं। भारत के लिए सिंगापुर की प्रासंगिकता बहुत पहले से रही है। सिंगापुर चाहता भी है कि भारत आसियान और पूर्वी एशिया में सक्रिय भूमिका निभाये। सिंगापुर ने ऐसे संकेत कई बार दिये हैं। भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत सिंगापुर है। पिछले वित्त वर्ष में सिंगापुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा था, जहां से 11.77 अरब डॉलर का निवेश आया था। दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग भी बहुत मजबूत है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है तथा उसके शानदार विकास

में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले दोनों देशों के मंत्रियों के बीच वार्ता के दौर भी चले थे। इन वार्ताओं में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था। उस समय सहयोग के ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया गया था, जिनका आसियान देशों के साथ चीन का गहरा व्यापारिक संबंध है, पर सीमा निर्धारण को लेकर विवाद भी गंभीर हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए सभी देशों को इस क्षेत्र में शांति बनी रहे तथा सभी देशों को समान अधिकार मिलें। चीन की वर्चस्ववादी नीति अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन गयी है। ऐसी स्थिति में दक्षिण-पूर्व एशिया के देश चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भारत अधिक सक्रिय हो ताकि संतुलन स्थापित करने में सहायता मिले। यह भारत के हितों के लिए भी सकारात्मक होगा। यह भी एक कारण है कि भारत 'एक्ट ईस्ट' की नीति पर आगे बढ़ रहा है। नीतिगत दृष्टि से देखें, तो भारत पांच 'एस' के सिद्धांत- सम्मिलन, संवाद, सहयोग, शांति एवं समृद्धि- को आगे रख कर चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जायेगी। इसलिए आसियान देशों के साथ सहकार बढाना बहुत आवश्यक है। भारत ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित कई छोटे द्वीपीय देशों के साथ मिलकर एक साझा संगठन बनाया है। सामुद्रिक आवागमन सुचारु रूप से चले और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए भारत ने सारण नीति बनायी है। ये सारे प्रयास हिंद-प्रशांत क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए ही किये जा रहे हैं।

उल्लेख किया गया है, लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर में चीन अपना वर्चस्व स्थापित करने पर आमादा है। उसने अपने आधिकारिक नक्शों में भी उस क्षेत्र को दर्शाया है। इससे वियतनाम और फिलीपींस जैसे अनेक आसियान देश नाराज हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भी भारत का दौरा किया था। हालांकि आसियान देशों के साथ चीन का गहरा व्यापारिक संबंध है, पर सीमा निर्धारण को लेकर विवाद भी गंभीर हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए सभी देशों को इस क्षेत्र में शांति बनी रहे तथा सभी देशों को समान अधिकार मिलें। चीन की वर्चस्ववादी नीति अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन गयी है। ऐसी स्थिति में दक्षिण-पूर्व एशिया के देश चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भारत अधिक सक्रिय हो ताकि संतुलन स्थापित करने में सहायता मिले। यह भारत के हितों के लिए भी सकारात्मक होगा। यह भी एक कारण है कि भारत 'एक्ट ईस्ट' की नीति पर आगे बढ़ रहा है।

नीतिगत दृष्टि से देखें, तो भारत पांच 'एस' के सिद्धांत- सम्मिलन, संवाद, सहयोग, शांति एवं समृद्धि- को आगे रख कर चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जायेगी। इसलिए आसियान देशों के साथ सहकार बढाना बहुत आवश्यक है। भारत ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित कई छोटे द्वीपीय देशों के साथ मिलकर एक साझा संगठन बनाया है। सामुद्रिक आवागमन सुचारु रूप से चले और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए भारत ने सारण नीति बनायी है। ये सारे प्रयास हिंद-प्रशांत क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए ही किये जा रहे हैं।

आज का इतिहास

1781 ग्रीटोन हाइट्स की लड़ाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सेना विजय हुई।

1781 अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध-जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने ग्रीन हाइट्स की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को जीत के लिए प्रेरित किया।

1813 डेनविल्ड्ज़ की लड़ाई में नेपोलियन की सेनाओं को फिर से प्रशिया और रूस ने हराया।

1901 अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकिनले, न्यूयॉर्क के बफेलो में पैन-अमेरिकन एक्सपोज़िशन में अलंकारवादी लियोन कोज़ीलोगोज़ को बुरी तरह घायल कर चुके थे।

1915 पहला युद्धक टैंक बनाया गया। इंग्लैंड में बने टैंक के इस पहले प्रारूप को लिटिल विलि के नाम से पुकारा गया।

1916 पहला सुपर मार्केट अमेरिका के टेनेसी में खुला।
1921 कनेक्टिकट में पुलिस क्लू क्लक्स क्लान में एक जांच कर रही है, जो कथित रूप से सदस्यों को एक शुद्ध एंग्लो सेक्सन सभ्यता के विचारों को संरक्षित करके सदस्यों की नियुक्ति कर रहे हैं।

1930 अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हिपालिटो यूगॉयन को जोस फेलिक्स उरिबुरु द्वारा एक सैन्य तख्तापलट में तैनात किया गया था।

1934 लंदन में रहस्यमय फिल्म चार्ली चैन ने वार्नर ओल्ड द्वारा अभिनीत की गयी।

1937 इल मज़ुको युद्ध के साथ स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ।
1946 संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव जेम्स एफ। बायर्सन ने जर्मनी के बाद के संबंध में घोषणा की, कि अमेरिका आर्थिक पुनर्निर्माण के अपोलिश का पालन करेगा।

1948 जुलियाना नीदरलैंड की महारानी बनीं।
1952 एक प्रोटोटाइप विमान इंग्लैंड के फर्नबोरो एयरशो हैम्पशायर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 29 दर्शकों और दो लोगों की मौत हो गई।

1955 तुर्की की एक भीड़ ने इस्तांबुल में जातीय यूनानियों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 5,000 से अधिक यूनानी-स्वामित्व वाले घरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा।

चंपाई सोरेन प्रकरण से झामुमो की राजनीति पर कोई असर नहीं!

आदिति फडणिस

इस महीने 10 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए सदस्य और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कोल्हान क्षेत्र में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। यह रैली दोनों नेताओं के बीच संबंध मजबूत करने और चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने जयशेदपुर से टेलीफोन पर बड़े उत्साह से कहा, 'चंपाई को भाजपा में लाना बहुत बड़ी सफलता है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व के अहंकार और उनकी मनमानी को दर्शाता है।'

झारखंड में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होने हैं। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में 14 विधानसभा सीट को कवर करने वाले कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी बहुत क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां भी शामिल है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस इलाके में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इस क्षेत्र में झामुमो के 11 विधायक, कांग्रेस के दो और एक निर्दलीय विधायक सरसू रॉय हैं। भाजपा के नेताओं को उम्मीद है कि वे चंपाई की मदद से झारखंड में सरकार बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

इस वर्ष की शुरुआत में चंपाई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसा तब हुआ जब झामुमो प्रमुख और पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जब हेमंत जेल से रिहा हुए तब उन्होंने फिर से अपने पद के लिए दावा

किया जिसे चंपाई सोरेन को खाली करना पड़ा। हालांकि चंपाई को जल संसाधन (जिसे उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था) सहित कुछ और विभाग भी दिए गए लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ जैसे कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

शाह देव ने बताया, 'अगर हेमंत ने उनसे विनम्रता से बात की होती और उनका अपमान नहीं किया होता कि वह महज एक 'अस्थायी मुख्यमंत्री' हैं तब संभवतः चंपाई दादा ने भी इस तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होती। अगर यह आदेश गुरुजी (झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन) की तरफ से आया होता तो उन्हें यह स्वीकार होता। हमलोग उनके सामने काफी युवा हैं, उनके सामने कोई विरोध नहीं कर सकता है। हेमंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था।'

हालांकि हेमंत के समर्थक इस बात का विरोध जमकर करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, 'वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत को राज्य में सरकार चलाने का जनादेश मिला। होना यह चाहिए था कि जब हेमंत को अदालत ने निर्दोष ठहराया तब चंपाई को खुद ही सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि उनके नेता को अदालत ने बरी किया है इसलिए वह पद उनके लिए छोड़ रहे हैं।' लेकिन चंपाई ने ऐसा नहीं किया।'

चंपाई ने स्थानीय मीडिया से कहा कि उन्होंने बेहद अपमानित सा महसूस किया जब उन्हें हटाने और हेमंत



चंपाई सोरेन

को चुनने के लिए विधायकों को बैठक, उन्हें बिना कोई जानकारी दिए हुए बुलाई गई। उन्हें यह भी कहा गया कि वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी जिसका नियुक्ति पत्र बांटने से भी उन्हें रोका गया।

कई मायने में चंपाई इस क्षेत्र के धाकड़ बजुर्ग नेता हैं। बिहार से झारखंड बंटवारे के नौ वर्ष पहले, वह 1991 में सरायकेला सीट के उपचुनाव में एक स्वतंत्र विधायक के रूप में चुने गए थे। वह शिबू सोरेन और रघुनाथ मुर्मु की प्रेरणा से झामुमो से जुड़े थे। रघुनाथ ने

संथाली पांडुलिपि पर काम किया था जिसे ओल चिकी कहते हैं।

21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन चंपाई ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। जाहिर है उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा, 'आप अपने खराब स्वास्थ्य के कारण सक्रिय राजनीति से दूर हैं और पार्टी के भीतर कोई ऐसा मंच नहीं था जहां मैं अपनी चिंताएं व्यक्त कर सकूँ। आपके मार्गदर्शन में, झारखंड आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। आप हमेशा मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे।'

झामुमो कार्यकर्ता चंपाई को शिबू सोरेन की छाया के रूप में याद करते हैं और उन्होंने वह पार्टी छोड़ी जिसे स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी। वह राज्य के एकमात्र ऐसे सोरेन मुख्यमंत्री थे, जिनका ताल्लुक शिबू सोरेन परिवार से नहीं था। भाजपा के शीर्ष आदिवासी नेताओं में शुमार बाबूलाल मरांडी ने चंपाई की पार्टी में आने का स्वागत किया है।

भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा ने भी एक्स पर लिखा, 'आदिवासियों पर बोटों की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। सत्ता के लालच में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। चंपाई का भाजपा में शामिल होना अच्छा साबित होगा

और यह पूरे देश में आदिवासियों को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।' भाजपा में शामिल होने से पहले ही चंपाई ने सबसे पहले आदिवासी लड़कियों की शादी, बांग्लादेश के घुसपैठियों से होने को लेकर चिंता जताई।

अब सवाल यह है कि क्या झामुमो के शीर्ष नेतृत्व में दरार आने के बावजूद पार्टी, आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा को पीछे छोड़ने के अपने संकल्प को और मजबूत से आगे बढ़ाएगी? या यह इसे कमजोर कर सकता है? झारखंड में आदिवासी पहचान के मुद्दे पर 27 किताबें लिख चुके आदिवासी कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगुंगा का मानना है कि चंपाई के जाने से हेमंत को मजबूती मिली है, न कि वह कमजोर हुए हैं।

उन्होंने रांची से बिजनेस स्टैंडर्ड को फोन पर बताया, 'भाजपा को 2019 में 28 में से केवल 2 अराश्रित आदिवासी सीट मिलीं और इसका एक कारण था आदिवासी समुदाय में यह धारणा बनने लगी कि आदिवासी भूमि, भाजपा सरकारों के कार्यकाल में खतरे में थी। भाजपा सरकारों ने इस दिशा में कई कदम उठाए लेकिन विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए भूमि बैंकों में आदिवासी भूमि को जोड़ने से आदिवासियों के बीच अपनी आजीविका और पहचान के संदर्भ में डर पैदा हुआ। एक आदिवासी के लिए, पुलिस हमेशा दोस्त नहीं होती बल्कि आमतौर पर दुश्मन होती है। वे हेमंत को पीड़ित के रूप में देखते हैं।'

चुनाव में अब मुश्किल से कुछ हफ्ते बचे हैं ऐसे में भाजपा भी अपनी स्थिति मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ ही झामुमो भी जल्द ही एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है।

सुप्रीम कोर्ट के उम्मीद जगाते फैसले

अशनी कुमार

हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की दमनकारी प्रक्रियाओं के कारण उपजी भय और बेचैनी की भावना के बीच देश की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए, सख्त दंड विधानों के तहत लाए गए मामलों में जमानत देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले स्वागत योग्य हैं और बड़ी राहत लेकर आए हैं। अभियुक्तों द्वारा लंबी कैद गुजारने के बाद आए फैसलों ने विचाराधीन कैदियों में अपनी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और निजता की अमानवीय वंचना के खिलाफ उम्मीद जगाई है। फैसलों को स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। मनीष कुमार सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (9 अगस्त, 2024) में न्यायालय ने अपने अधिदेश की व्याख्या की 'संविधान और कानून के शासन के पक्ष में झुकना, जिसकी स्वतंत्रता एक अंतर्निहित मार्ग है।' इसमें आगे लिखा गया है कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद', जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार निहित है। सिसोदिया प्रकरण में संवैधानिक स्थिति की अपनी सुस्पष्ट व्याख्या के बाद, न्यायालय ने कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय (27 अगस्त, 2024) मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई के माध्यम से दोहराया कि 'अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रतिबंधों से श्रेष्ठ है' और यह कि 'किसी अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना मुकदमे के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।' पुनः, प्रेम प्रकाश बनाम यूनिनय ऑफ इंडिया (28 अगस्त, 2024) में, न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के माध्यम से कहा, 'व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा एक नियम है और वंचना अपवाद है।।' न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'मुकदमे के शीघ्र प्राप्ति होने की आशा में किसी व्यक्ति को असीमित समय के लिए सलाखों के पीछे रखना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से वंचित करना होगा।।' न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने विजय नायर बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2 सितंबर, 2024) में न्यायालय ने पहले के निर्णयों को निरस्त कर दिया और लंबे समय तक हिरासत में रहने और शीघ्र सुनवाई के आरोपी के अधिकार के आधार पर जमानत दे दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 45 की व्याख्या करते समय, न्यायालय ने प्रेम प्रकाश मामले में कहा कि उसमें 'विश्वास करने के उचित आधार' शब्दों के लिए, 'न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि 'क्या आरोपी के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है।' 'जांच के दौरान एकत्र की गई उचित सामग्री के आधार पर' पीएमएलए के तहत हिरासत में आरोपी के बयान के संबंध में, न्यायालय ने दोहराया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति 'ऐसा बल्कि नहीं है जिसे स्वतंत्र दिमाग से काम करने वाला माना जा सके' और यह कि 'इस तरह के बयानों को स्वीकार्य बनाना बेहद असुरक्षित होगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई निष्पक्षता और न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगी।' इस संदर्भ में, न्यायालय के फैसले से सरकार को बिना जमानत के आरोपी की हिरासत को उचित अधिकतम अवधि को अनिवार्यतः सुनिश्चित करने के लिए कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करने को राजी होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण फैसलों का महत्व न केवल उनकी असंदिग्ध संवैधानिक गुणवत्ता में निहित है बल्कि उसे विद्वान जजों की बौद्धिक निष्ठा में भी देखा जा सकता है। ये वो न्यायाधीश हैं जिन्होंने कानून को हमेशा न्याय के साथ जोड़ा है और स्वतंत्रता की आवाज पर संवैधानिक मुहर लगाई है। ये फैसले समाज को स्थिर करनेवाली ताकतों के हित में कानून के प्रति आस्था को फिर से मजबूत बनाएंगे। इन सभी फैसलों का सार यही है कि अन्याय के खिलाफ हर आवाज को सुना जाएगा और अनुचित ढंग से लागू किए गए कानून के आगे न्याय को झुकाया नहीं जा सकेगा। देश की सर्वोच्च न्यायाधिक संस्था द्वारा सुनाए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि न्याय ही सर्वोच्च है और गैरजवाबदेह सत्ता और आजादी के बीच तनाव का फैसला अंततः स्वतंत्रता के हक में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की सर्वोच्चता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उसने इस सिद्धांत की पुष्टि की है कि 'भले ही आसमान गिर पड़े लेकिन न्याय होना चाहिए।'

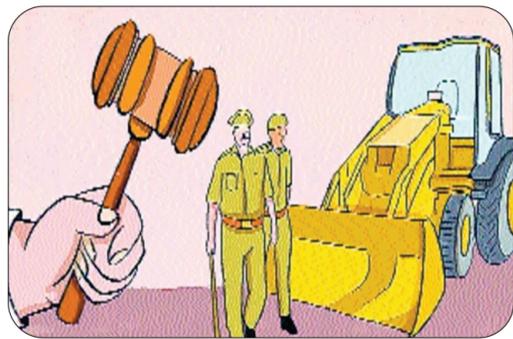
अलोकतांत्रिक 'बुल्डोजर न्याय' खत्म होना चाहिए

तिपिन पक्की

हमारे संविधान और नागरिकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 'बुल्डोजर न्याय' देने की बर्बर और सांप्रदायिक प्रथा को पहचान लिया है। यह कि वह कई वर्षों से न्याय के इस तरह के मजाक को अनदेखा कर रहा था। यह हमारे लोकतंत्र पर एक धक्का रहेगा। जैसा कि सर्वविदित है, इस प्रथा के आविष्कारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें कम से कम हालिया लोकसभा चुनावों के नतीजों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। समाज में उनके 'शानदार' योगदान के लिए उनके प्रशंसकों ने उन्हें 'बुल्डोजर बाबा' का उपनाम दिया था। उनका फरमान सरल था कि गैर-कानूनी गतिविधियों में लिस लोगों या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के घरों या इमारतों को बुल्डोजर से उड़ा दो, लेकिन इस शर्त के साथ कि आरोपी केवल एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। अगर आरोपी किसी अन्य समुदाय से संबंधित था, तो ऐसी कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

इस काम का तरीका यह था कि आरोपी या उसके परिवार के घर या इमारत की पहचान की जाए। इसके निर्माण में की गई कुछ अनियमितताओं या कुछ दस्तावेजों की कमी का पता लगाया जाए और बिना कोई नोटिस दिए या अदालत से ध्वस्तीकरण के आदेश प्राप्त किए तत्काल 'न्याय' किया जाए। यहां तक कि एक बच्चा भी इस कार्रवाई के पीछे के मकसद को समझ सकता है और यह तथ्य कि इस तरह के ध्वस्तीकरण महज संयोग नहीं थे। बुल्डोजर को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए भेजा गया था।

सरकार ने कथित तौर पर एक विशेष समुदाय के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अभियोजक, न्यायाधीश और जल्लाद की भूमिका निभाई। हम एक



समन्न लोकतंत्र के रूप में खुद पर गर्व करते हैं, जिसके कानून प्रवर्तन अंग ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह भी दुःख और निराशाजनक है कि मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी इस तरह की मनमानी के प्रति आंखें मूंद लीं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके पास ऐसे गंभीर मुद्दों के लिए समय नहीं है। यह सवाल किया जाना चाहिए था कि पूरे परिवार और हमेशा गरीब परिवार को क्यों पीड़ित और बेघर होना पड़ा, जबकि परिवार का एक सदस्य भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं पाया था?

हाल ही में एक अनोखे मामले में, एक संदिग्ध के मकान मालिक का घर सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उसने घर किराए पर लिया था। और फिर भी हमारी पुलिस और न्यायपालिका मुकदमों को बनी रही। लेकिन योगी के अनुयायी गरीबों के घरों को ध्वस्त करने पर अपनी खुशी जाहिर करने से नहीं चूके। उन्होंने सोशल मीडिया पर योगी की तारीफों की बाढ़ ला दी और इस तरह की और कार्रवाई की मांग की। योगी की तारीफों से उत्साहित होकर कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बर्बर प्रथा की नकल की। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, असम और

हरियाणा शामिल हैं। यहां तक कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महाराष्ट्र में पूर्व एम.वी.ए. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जैसे कुछ गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी यह बीमारी लग गई, जिन्होंने सोचा कि इस तरह का तत्काल 'न्याय' करना उचित है।

अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत देर से और बहुत कम है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति

के.वी. विश्वनाथन की सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने कहा, 'किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।' पीठ ने आगे कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा-निर्देश तय करने का प्रस्ताव करती है, ताकि उठाए गए मुद्दों से जुड़ी चिंताओं का समाधान किया जा सके। स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया पूरी तरह अपर्याप्त है। क्या किसी भी इमारत को गिराने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए पहले से ही कानून नहीं हैं? दिशा-निर्देश तय करने की क्या जरूरत है?

उन लोगों का क्या होगा, जिन्होंने इस तरह के घोर अन्याय को झेला है। उन्हें कैसे मुआवजा दिया जा सकता है और उन राजनेताओं और अधिकारियों का क्या, जिन्होंने अवैध रूप से ऐसे घरों को गिराया है? वे जाहिर तौर पर बेखोज घूमेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया होता और दोषियों को सजा दी होती, तो वह गंभीर लगता।

जातीय जनगणना की घोषणा हो सकती है जल्द!

विजय विद्रोही

जातीय जनगणना का परोक्ष रूप से समर्थन संघ ने कर दिया है। यहां तक कि कोटा में कोटा यानी वर्गीकरण पर भी संघ ने सर्वसम्मति की बात कही है। अब इसके बाद तो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का रास्ता तैयार हो गया है और मोदी सरकार जातीय जनगणना की घोषणा करेगी भी कर सकती है। सवाल उठता है कि क्या यह घोषणा अगले 10-20 दिनों में हो सकती है या प्रधानमंत्री मोदी के मन में कुछ और ही मंथन चल रहा है।

कहा जा रहा है कि मोदी अगर जातीय जनगणना की घोषणा अगले 10-12 दिनों में कर देते हैं तो राहुल गांधी के हाथ से जातीय जनगणना का बहुत बड़ा मुद्दा छिन जाएगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इस मुद्दे की फसल नहीं काट पाएगी। चूंकि जनगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ से 2 साल लगते हैं लिहाजा अगले 2 सालों तक कम से कम जातीय जनगणना और उससे जुड़े आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है।

उधर राहुल गांधी इसे समझ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का मतलब एस.सी., एस.टी. के साथ ओ.बी.सी. का नया कॉलम जोड़ना भर नहीं है। कांग्रेस तो सभी जातियों, उपजातियों की संख्या के साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का ब्यौरा भी चाहती है। ब्यौरा इसलिए चाहती है कि उसके आधार पर नए सिरे से आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए, नए सिरे से योजनाएं बनाई जा सकें और नए सिरे से पैसों का वितरण किया जा सके। इतने सारे आंकड़े आएं तो जाहिर है कि जातियों के नए सिरे से समीकरण बनेंगे। सियासी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा या घटेगा।

आरक्षण की मौजूदा 50 फीसदी की सीमा भी तोड़नी पड़ेगी। दिलचस्प बात है कि इसका फायदा तो विरोधी दल उठा ले जाएंगे लेकिन अगर कुछ ऊंच-नीच हुई तो सत्तासीन दल या गठबंधन को अंजाम भुगतना पड़ेगा क्योंकि फैसले तो उसे ही लेने होंगे। ऐसे में गठबंधन दलों की सामाजिक न्याय की राजनीति के भी पूरी तरह से छितराने का खतरा पैदा हो जाएगा। कुल मिलाकर जातीय



जनगणना के नए आंकड़े कई मायनों में विस्फोटक साबित हो सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि जातीय जनगणना की घोषणा करना और आंकड़ों को जारी करने में अंतर को समझना जरूरी है। ऐसा फार्मुला चिराग पासवान ने भी सामने रखा है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना सरकार करवाए लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करें।

अलबत्ता उन आंकड़ों का प्रयोग नए सिरे से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए योजनाएं बनाने में करें। यहां जानकार रोहिणी कमिशन रिपोर्ट का हवाला देते हैं। उनका कहना है कि पिछड़ी जातियों में कोटा में कोटा की संभावनाएं तलाशने के लिए बिठाए गए कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है लेकिन सरकार न तो उसे सार्वजनिक कर रही है और न ही लागू कर रही है। अलबत्ता विश्वकर्मा योजना लागू करने के लिए इस कमीशन के आंकड़ों का इस्तेमाल जरूर किया गया। अब यह काम जब रोहिणी कमिशन को लेकर हो सकता है तो जातीय जनगणना को लेकर क्यों नहीं हो सकता।

रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि ओ.बी.सी. में कुल 2600 जातियां आती हैं। इसमें से 900 के लगभग जातियों को ओ.बी.सी. आरक्षण का शून्य फीसदी लाभ भी नहीं मिला। करीब 950 जातियों को सिर्फ अर्द्धाई फीसदी ही लाभ मिला। बाकी का 97.5 फीसदी लाभ ऊपर की करीब 600 जातियों उठा ले गईं। तय है कि जातीय जनगणना में भी दलितों और आदिवासियों को लेकर ऐसे

ही तथ्य सामने आने वाले हैं। अब रोहिणी कमिशन ने ओ.बी.सी. की 4 श्रेणियां बनाने की सिफारिश की है। मोदी सरकार कोटा में कोटा कर जाट, यादव, माली जैसी प्रभावशाली जातियों को नाराज नहीं करना चाहती। अब वही सरकार किस तरह दलितों और आदिवासियों में वर्गीकरण के लिए सहमत हो जाएगी। जाहिर है नहीं होगी। तो क्या साफ है कि आंकड़े भी सामने नहीं आएंगे।

कुछ जानकारों का कहना है कि निचली जातियां अभी बिखरी हुई हैं। उनके नेता भी नहीं मिलते हैं लेकिन नए समीकरण बनेंगे तो जातियों के नए नए नेता पैदा हो जाएंगे जो भाजपा जैसी राष्ट्रीय दल को तंग ही करेंगे। वैसे भी भाजपा चाहती है कि (संघ भी यही चाहता है) गैर-मुस्लिम कुल मिलाकर हिंदू की तरह वोट दे। अभी देश के 80 फीसदी हिंदुओं में से करीब 50 फीसदी भाजपा को वोट देता है। भाजपा और संघ इसमें विस्तार चाहते हैं। अब अगर जातीय जनगणना हो गई तो जातियां जातियों में बंटकर वोट देना शुरू कर देंगी और हिंदुत्व का सारा एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। जाहिर है कि भाजपा इतना बड़ा सियासी जोखिम क्यों उठाना चाहेगी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले हुए उतर भारत के राज्यों के विधानसभा चुनाव बताते हैं कि कुछ जातियों की नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ रही है।

राजस्थान में जाट और राजपूत छिटके हैं तो ऐसा ही कुछ हाल यू.पी. में भी देखा गया है तो क्या संघ को समझ आ रहा है कि जातीय जनगणना कराने पर सहमति देकर ऐसी जातियों की घर वापसी संभव हो सकती है। खैर, अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। एक बात तय है कि संघ ने भाजपा आलाकमान से सलाह के बिना जातीय जनगणना पर बयान नहीं दिया होगा। बात भी हुई होगी और शब्दों का चयन भी चर्चा के बाद किया गया होगा। संघ के प्रचार प्रमुख ने अपने मुंह से कहीं भी जातीय जनगणना का नाम नहीं लिया है। उल्टे चुनावी लाभ से नहीं जोड़ने की बात कर कांग्रेस को श्रेय नहीं लेने देने का रास्ता तैयार करने की कोशिश की है।

लाल चौक से भाजपा उम्मीदवार को मिल रहा समर्थन बड़े बदलाव के संकेत

नीरज कुमार दुबे

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की ओर से नामांकन दाखिल किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाल चौक श्रीनगर से भाजपा उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हम आपको बता दें कि इंजीनियर एजाज हुसैन भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं में शुमार हैं। हम आपको याद दिला दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पहला चुनाव डीडीसी का हुआ था और उस दौरान इंजीनियर एजाज हुसैन ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर घाटी में पहली बार कमल खिला दिया था। भाजपा को उम्मीद है कि इंजीनियर एजाज हुसैन की लोकप्रियता का फायदा उसे विधानसभा चुनावों में भी होगा। हम आपको बता दें कि इंजीनियर एजाज हुसैन के साथ बड़ी संख्या में घाटी के युवा हैं और डीडीसी सदस्य के रूप में भी उनके कार्य को काफी सराहा जाता है। लोगों की मदद के लिए उनका हमेशा उपलब्ध रहना उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा लाल चौक से भाजपा का उम्मीदवार इसलिए भी मायने रखता है कि यह वही इलाका है जहां एक समय आतंक और अलगाववादियों का राज था लेकिन लाल चौक पर आज शान से आसमान को छूता तिरंगा लहरा रहा है और वहां अब पर्यटकों का जमावड़ा बिना किसी खौफ के लगता है। लाल चौक पर जहां पहले शाम के बाद कोई नहीं दिखाई देता था आज वहां देर रात तक चहल पहल रहती है और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को देखकर लोग कश्मीरी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होते हैं। हम आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता के रूप में जब तिरंगा यात्रा का लाल चौक तक नेतृत्व किया था तब वहां तिरंगा फहराने का मातलब जान से खेलना था लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर ऐसा बदला कि आज लाल चौक का शांत और खुशहाल नजारा पूरे कश्मीर के बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप हाल ही में कभी लाल चौक गये होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे स्पष्ट सिटी अभियान के तहत इस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया है। इस क्षेत्र में किये गये विकास के बलवृत्ते भाजपा को उम्मीद है कि यहां की जनता इस बार परिवारवादी दलों की बजाय उसका साथ देगी। भाजपा को उम्मीद है कि उसके युवा प्रत्याशी यह सीट जीतकर विधानसभा में अवश्य ही पहुँचेंगे। जहां तक इंजीनियर एजाज हुसैन की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले एक भव्य रोट शो निकाला। इस दौरान प्रभासाक्षी से बात करते हुए इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि 70 साल तक राज करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घाटी के युवा और अन्य लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के जरिए ही विकास देखा है। वहीं इंजीनियर एजाज के समर्थकों ने भी कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा ही जीतेगी तथा एनसी और पीडीपी को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में, 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को मतदान होना है जबकि मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।





ट्रेंडी और स्टाइलिश लगने के लिए चुनें ये फैब्रिक, गर्मी में भी रहेंगे कूल एंड कंफर्टेबल

गर्मियों में हम सब ज्यादातर हल्के और आरामदायक कपड़े पहनते हैं। बता दें कि गर्मी के मौसम में आप अपने स्टाइल के साथ सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जानिए कि किस तरह के फैब्रिक गर्मियों में आपको कूल और कंफर्टेबल लुक देंगे।

जब भी गर्मियों में आरामदायक फैब्रिक्स की बात आती है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सबसे पहला नाम कॉटन का होता है। लेकिन आपके वॉर्डरोब में शर्ट से लेकर कुर्ते, टॉप से लेकर बॉटम वेयरस भी कॉटन में हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कॉटन के कपड़ों को एक्सपोज़र केयर की जरूरत होती है। साथ ही कॉटन फैब्रिक थोड़े महंगे भी होते हैं। हालांकि अपने स्टाइल के साथ सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट गर्मी के मौसम में ही होते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मी के मौसम में किस तरह के फैब्रिक आपको कूल और कंफर्टेबल लुक देंगे।

कॉटन
कॉटन फैब्रिक में सबसे अच्छी बात यह होती है कि ब्रीदेबल होते हैं। जिसका मतलब इसे पहनने के बाद आपको ऊबन महसूस नहीं होगी। क्योंकि गर्मियों में यह आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। अन्य फैब्रिक के मुकाबले कॉटन परसोने को आसानी सोख लेता है। कॉटन आउटफिट्स डेरो स्टाइल और कलर में अवेलेबल होती है। इस फैब्रिक को आप कॉलेज से लेकर ऑफिस, फिटी पार्टी से लेकर डे आउटिंग या फिर नाइट पार्टीज में भी कैरी कर सकती हैं। हालांकि इनके साथ सिर्फ यही समस्या होती है कि इन कपड़ों को बिना ऑयलरन के नहीं पहना जा सकता है। लेकिन कॉटन-पॉलिस्टर मिक्स आउटफिट्स में यह समस्या नहीं होती है। साथ ही लंबे समय तक पहनने के बाद भी इनमें से बदबू नहीं आती है। कॉटन कपड़ों पर लगे दाग-धब्बों पर लगे दाग भी आसानी से छूट जाते हैं।

लिनन
गर्मियों के लिए आरामदायक फैब्रिक्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर लिनन है। कॉटन की तरह ही यह भी हल्का और ब्रीदेबल होता है। लिनन भी परसोने और नमी को आसानी से सोख लेता है। बता दें कि रिक्लस फैब्रिक की पहचान हल्के रिक्लस है। यही इन्हें खास बनाते हैं। लेकिन लिनन फैब्रिक की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनको आप बिना ऑयलरन के भी पहन सकते हैं। साथ ही यह आपको वलासी लुक देने का काम करता है। इनमें बहुत ही सूडिंग कलर्स आते हैं, जो गर्मियों के लिए काफी बेस्ट होते हैं।

रेयॉन
रिक्ल फैब्रिक का सस्ता और अच्छा वर्जन रेयॉन है। यह पतले रेशे से बना होता है। जिसके कारण यह काफी लाइटवेट भी होता है और गर्मियों में यह शरीर में चिपकता भी नहीं है। कंफर्टेबल और ब्रीदेबल होने की वजह से इसको स्पोर्ट्स वेयर से लेकर समर ड्रेसिज तक में वैरायटी देखी जा सकती है। हालांकि रेयॉन के कपड़ों को गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। क्योंकि गर्म पानी से यह सिकुड़ जाता है। इसलिए इसको नॉर्मल पानी से ही धोना चाहिए।

नायलॉन
अधिकतर एक्टिव वेयर या एथलेटिक्स वेयर से बनाए जाते हैं। यह काफी लाइटवेट भी होते हैं। वही परसोने आदि से गीला होने पर यह जल्दी सूख भी जाता है। साथ ही नायलॉन स्ट्रेचबल भी होता है। बता दें कि लंबे इस्तेमाल के बाद भी इस फैब्रिक वाले आउटफिट्स जल्दी खराब नहीं होते।



अगर ऑफिस में आपका कलीग आपके द्वारा किए गए काम का पूरा श्रेय खुद ले लेता है तो उससे डील करने के लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकती हैं।

जी वन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बेहद आवश्यक होता है। आप ऑफिस में रहते हुए अपने काम को कितनी दक्षता या कुशलता के साथ करते हैं, यह बेहद ही अहम होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सारी मेहनत आप करते हैं और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। ऐसे में निराशा या दुख होना लाजमी है। अगर ऐसा बार-बार होता है तो व्यक्ति का मनोबल टूटता है। साथ ही उसकी प्रोफेशनल लाइफ सबसे से से भी बाधा पैदा होती है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा हो और आप खुद को निराशा व अंधकार में महसूस कर रही हो। लेकिन इस दौरान आपको नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक अप्रोच के जरिए उस व्यक्ति को समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है, जो आपके द्वारा किए गए सारे काम का श्रेय ले रहा है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे लोगों को हैंडल करने के कुछ आसान टिप्स -

खुद को रखें शांत
यह सबसे पहला व जरूरी टिप है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि कोई आपके काम का श्रेय ले लेता है तो स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आगा ही। लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर करना अच्छी बात



बेहद ही अहम होता है ऑफिस में अपने काम को दक्षता या कुशलता के साथ करना

नहीं है। आपकी यह छोटी सी हरकत आपकी छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। बेहतर होगा कि आप अपनी प्रोफेशनल इमेज को बनाए रखें और हर किसी के सामने प्रतिक्रिया देकर अपना नाम खराब न करें।

वरिष्ठों को करें शामिल
ऑफिस का माहौल बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह न केवल काम से संबंधित कई चीजें सिखाता है बल्कि व्यवहार से लेकर निर्णय लेने की क्षमता तक बहुत सी चीजें सिखाता है। इसलिए, अगर आपको ऑफिस में क्रेडिट चोरी होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो समस्या को सुलझाने के लिए कुछ सबसे भरोसेमंद वरिष्ठ कर्मचारियों से संपर्क करना अच्छा होता है। आप उन्हें सीधे शामिल होने और समाधान प्राप्त करने में मदद करने के लिए

कह सकते हैं। जब आप वरिष्ठ कर्मचारियों को इसमें शामिल करती हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको उनसे सही समाधान मिल जाए।

खुद को करें सीमित
अक्सर क्रेडिट चोरी होने की समस्या तब अधिक होती है, जब आपके कार्य और कार्य करने के तरीके के बारे में अधिकतर लोगों को पता होता है। ऐसे में आपके काम के कंलीट होने के बाद अन्य व्यक्ति उसका क्रेडिट ले जाता है। इसलिए, ऑफिस में अपने व्यवहार को सीमित रखें। ध्यान रखें कि ऑफिस में आप काम करने के लिए आए हैं और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखें। जब आप बहुत अधिक फंडली नहीं होते हैं तो कोई भी सहकर्मी आपके काम के बीच में आने का साहस जल्द नहीं करता है।



अगर सेलेब्स की तरह करना है मेकअप तो यूं करें अपनी स्किन को तैयार

ह र कोई बॉलीवुड सेलेब्स को देखकर मुग्ध हो जाता है। ऐसा बॉलीवुड का सेलेब्स होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सुंदरता के कारण होता है। खासकर तब, जब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस की हो... उनकी सुंदरता तो देखने लायक होती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस की सुंदरता को देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा इनके अच्छे मेकअप के कारण होता है। लेकिन जब यही मेकअप हम आम लड़कियां यूज करती हैं तो फिर सेलेब्स लुक क्यों नहीं आ पाता। ऐसा अनप्रिपेयर्ड स्किन के कारण होता है। दरअसल सेलेब्स की स्किन ही काफी अच्छी होती है जो मेकअप कर के और अधिक खूबसूरत हो जाती है। ये वैसे ही बात है कि आप बाइक चलाना भी तो आना चाहिए। इसी तरह से मेकअप के साथ भी है। मेकअप कितना ही अच्छा क्यों हो... अगर स्किन खराब होगी तो कोई फायदा नहीं होगा।

तो आपको मालूम चल गया कि आप कहां गलती कर रही थीं। तो इस आमना वहाब बताती हैं कि मेकअप करने से पहले चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो कर मेकअप एप्लाइ करना चाहिए। इन जरूरी स्टेप्स के बारे में इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं। क्योंकि स्किन सही तो समझ लेना कि सुंदर दिखने की आधी जंग आपने जीत ली है।

शुरुआत करें क्लेजिंग से
सुंदर दिखने की शुरुआत साफ चेहरे से शुरू होती है। इसलिए हमेशा चेहरे को फेसवॉश से साफ करना ही काफी नहीं है। क्लेजिंग केसा है ये भी आपके चेहरे के लिए काफी जरूरी है। दरअसल सही क्लेजिंग से आपके चेहरे पर मेकअप के लिए साफ कैनवस देती है। आमना कहती हैं, जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें हमेशा लैडर बनानेवाला फेस वॉश लेना चाहिए। रूखी त्वचा वालों को हाइड्रेटिंग क्लेजिंग का चुनाव करना चाहिए।

स्किन के अनुसार पीएच वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें
स्किन स्पेशलिस्ट क्लेजिंग चुनते वक्त पीएच लेवल का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह देते हैं। वे बताते हैं, हम बिजी शेड्यूल होने के कारण की बार पानी पीना भूल जाते हैं जिसके कारण स्किन में नमी की कमी हो जाती है। इस नमी से बचने के लिए हमेशा अपने स्किन के अनुसार पीएच लेवल देखकर क्लेजिंग चुनना चाहिए।

इसके बाद टंडक दें
इसके बाद अपनी स्किन को टंडक दें। आमना बताती है कि मेकअप शुरू करने से 15 मिनट पहले चेहरे को टंडक देने के लिए बर्फ के टुकड़ों से मालिश करनी चाहिए। इससे पोर्स बंद हो जाते हैं और परसोना नहीं निकलता है जिससे मेकअप ज्यादा समय तक टिका रहता है। इससे मेकअप पोर्स के अंदर भी नहीं जाते और रेशेज होने का खतरा भी टल जाता है। इसलिए हमेशा मेकअप करने से पहले चेहरे की बर्फ से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे मेकअप से किसी भी तरह की स्किन इफेक्शन की समस्या नहीं होती है। स्किन स्पेशलिस्ट भी ऑयली चेहरे के लिए बर्फ की मालिश को अचूक उपाय बता चुके हैं। इससे मॉइस्चराइजर त्वचा के भीतर समा जाता है और स्किन के ऑयली दिखने की समस्या कुछ घंटों के लिए खत्म हो जाती है।

मॉइस्चराइजर का करें सही तरीके से इस्तेमाल
मेकअप की तैयारी का सबसे जरूरी स्टेप है अपने चेहरे की नमी को ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए लॉक करना तभी चेहरे पर पानी दिखेगा मतलब कि नमी दिखेगी और चेहरा ग्लोइंग नजर आएगा। इसलिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल अच्छे से करें। बर्फ से चेहरे की मालिश करने के बाद चेहरे की मॉइस्चराइजर से मालिश करें। इससे मॉइस्चराइजर स्किन के अंदर जाएगा और ज्यादा समय तक टिके रहेगा साथ ही स्किन के मासपेशियों में रक्तसंचार भी बढ़ेगा। ब्यूटी एकस्पर्ट आमना मॉइस्चराइजर से चेहरे की सर्क्युलर मोशन में मालिश करने की सलाह देती है। फिर इसके बाद ऊपरी दिशा में मतलब उंगुलियों को नीचे से ऊपर ले जाते हुए मालिश करनी चाहिए। इससे चेहरे पर मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से लग जाएगा।

ऐसे लगाएं प्राइमर
उम्र बढ़ने के साथ हॉटों के किनारे में सिलवटें दिखना शुरू हो जाती हैं। इन्हें आप प्राइमर का सही तरीके से यूज कर छुपा सकती हैं। मेकअप

इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर आप प्राइमर का सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं तो इससे चेहरा चिकना नजर आता है और चेहरे पर से अनचाही झुर्रियां और सिलवटों को भी आप छुपा सकती हैं। आमना कहती है, ऐसे प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सोडियम हाइड्रोलुरेट मिला हो। क्योंकि ये झुर्रियों को काफी अच्छे तरीके से छुपा देता है। तो ये तो था बेस्ट सेलेब लुक पाने के मेकअप टिप्स की तैयारी। इन्हें फॉलो कर आप मिनीमम मेकअप भी करके सेलेब लुक पा सकेंगी। तो आज से ही इन टिप्स को फॉलो करना शुरू करें और बने पार्टी के जान।

वीकेंड पर बच्चों के लिए प्लान करें मजेदार एक्टिविटी, मौज-मस्ती के साथ बढ़ेंगी बॉन्डिंग

इन दिनों पेरेंट्स अपने कामकाज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ समय बिताना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। समय की कमी के कारण जब पेरेंट्स बच्चों के साथ समय नहीं बिताते तो वह अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने में फेल होते जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बातों को अपनाते हैं तो आप बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं। वीकेंड पर आप और आपका बच्चा दोनों ही फी होते हैं ऐसे में आप इस दौरान बच्चों के साथ इन मजेदार एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं।



ट्रेजर हंट करें प्लान

बच्चों के मन में उत्सुकता बनाए रखने के लिए आप ट्रेजर हंट प्लान कर सकते हैं। इसे प्लान करने के लिए बच्चों की फेवरेट चीजों को छुपाएं और फिर कुछ चिटस बनाएं जिसे पढ़कर बच्चे को गिफ्ट ढूँढ़ने की हिंट मिले। यह आपके बच्चे की रुचि के बारे में जानने का भी एक शानदार तरीका हो सकता है।

सितारों को देखें

इस मजेदार पारिवारिक एक्टिविटी को शुरू करने के लिए, इंटरनेट से एक स्टार चार्ट डाउनलोड करें। फिर अपने यार्ड में एक स्थान बँटें जहाँ से आकाश के स्पष्ट नजारे दिखते हैं, और यह देखें कि दिन रात का आकाश कैसे बदलता है।

मैजिक ट्रिक

फेमिली एक्टिविटी के लिए आप बड़ी स्क्रीन पर बच्चों के साथ जादू देख सकते हैं। कुछ ऐसी भी मैजिक ट्रिक्स हैं जिसे आप अपने बच्चे के साथ सीख सकते हैं और दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं।

घर में ही करें कैम्पिंग

बच्चों के साथ आप घर में ही कैम्पिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए घर के गार्डन या छत पर टेंट लगाएं और फिर बच्चों के साथ उस टेंट में एंजॉय करें। इस दौरान आप बच्चों के फेवरेट गेम खेल सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। ये काफी मजेदार हो सकता है।

टाई एंड डाई

बच्चों के साथ आप टाई डाई भी कर सकते हैं। इसके लिए नई शर्ट, मोजे, कंबल और तर्किए के केंस पर कुछ डिजायन कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे भी कुछ नया सीखते हैं।

अनिल देशमुख पर सीबीआई ने दर्ज किया नया केस

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कथित तौर पर भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया। इस मामले में कथित तौर पर यह आरोप शामिल है कि गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान देशमुख ने जलगांव में पुलिस अधिकारियों पर भाजपा नेता गिरीश महाजन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला था। देशमुख ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की साजिश है। राकांपा नेता पहले से ही कथित भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई मामले और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा मेरे खिलाफ एक और आधारहीन मामला दर्ज किया गया है। यह साजिश इसलिए शुरू हुई है क्योंकि फडणवीस लोगों के जनानदेश को देखकर घबरा गए हैं।

बाढ़ प्रभावित तेलंगाना और आंध्र का दौरा करेंगे शिवराज

नई दिल्ली। दक्षिण के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौजूदा बाढ़ की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है जो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर मौके पर ही आकलन करेगी और तत्काल राहत के लिए सिफारिशें करेगी। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों की राज्यों का दौरा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें ये आदेश दिया गया है। शिवराज ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मैं, गुरुवार और शुक्रवार को आंध्रप्रदेश, तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर वहां भाइयों-बहनों और किसानों से चर्चा करूंगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति आकलन के लिए विजयवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा।

हरियाणा भाजपा में कैबिनेट मंत्री रणजीत का इस्तीफा

चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का नाम शामिल नहीं है। इसके बाद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह चौटाला भाजपा द्वारा राजिया विधानसभा से टिकट न दिए जाने से नाराज थे। भाजपा आलाकमान ने आगामी हरियाणा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची से नौ मौजूदा विधायकों को हटा दिया है। राजिया सीट से बीजेपी ने शीशपाल कंबोज को मैदान में उतारा है। भाजपा नेता रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं राजिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। यह मेरे क्षेत्र के लोगों का फैसला है। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बीजेपी के रतिया विधायक लक्ष्मण नाप ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 5 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के लिए टिकट देने से भी इनकार कर दिया गया था।

जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनाए सरकार : बसपा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह बुलडोजर राजनीति छोड़कर जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनाए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, उप्र के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों आदि पर हमला कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाये। मजदूर और गरीब लोग जंगली जानवरों के हमलों के डर की वजह से अपने पशुओं के चारे का प्रबन्ध तथा मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा, साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की भी रणनीति बनाये। इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की बजाय यह मामला अदालत पर छोड़ देना चाहिये, जहाँ न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।

महाराष्ट्र में सीएम का फैसला चुनाव बाद होगा : संजय राउत

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से तेज हैं। हालांकि, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर खींचतान भी देखने को मिल रही है। लेकिन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का दावा है कि उसमें शामिल तीनों दल भाजपा और शिंदे गुट को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत बांध में हो सकती है। संजय राउत ने कहा कि हम सभी का हलाक मकसद यह है कि महायुक्ति के नेतृत्व वाली सरकार को हटाना है। उन्होंने कहा कि पवार साहब 100 प्रतिशत सही हैं। यह तीन दलों की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम बाद में किसी भी समय सीएम पद के बारे में बात कर सकते हैं।

शिवाजी की मूर्ति ढहने पर हर व्यक्ति से मांगनी चाहिए माफी : राहुल

महाराष्ट्र के डीएन में है कांग्रेस की विचारधारा

मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौर पर हैं। सांगली जिले में रैली में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस विचारधारा का गढ़ है, यहां के लोगों में हमारी पार्टी का डीएन है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति होती थी, लेकिन आज भारत में वैचारिक लड़ाई है। हम सामाजिक प्रगति चाहते हैं लेकिन वे (भाजपा) चाहते हैं कि केवल चुनिंदा लोगों को ही सारा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। उन्होंने दावा किया कि मैंने लोकसभा में कहा है कि कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। हमारा गठबंधन इसे पूरा करेगा।



महाराज, फुले जी समेत कई लोगों ने महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश को जीने का तरीका दिया, प्रगति और प्रेरणा दी। इससे पहले राहुल गांधी ने सांगली जिले में कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की आदमकद प्रतिमा का बृहस्पतिवार को अनावरण किया। कदम ने महाराष्ट्र में कई विभागों में मंत्री पद संभाला करेगा।

था। कई वर्षों तक पलूस-काडेगांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कदम की प्रतिमा जिले के वांगी में स्थापित की गई है। गांधी ने वांगी में दिवंगत नेता को समर्पित एक संग्रहालय का भी दौरा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रभारी रमेश चेत्रिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब शेरारट इस कार्यक्रम में मौजूद थे। गांधी का एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। सुबह राहुल ने नांदेड में दिवंगत सांसद वसंत चव्हाण के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की।

राहुल गांधी के कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे ने बनाई दूरी

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के सांगली जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संबोधित सार्वजनिक बैठक में शामिल नहीं हुए, जहां राहुल ने महाराष्ट्र के दिवंगत मंत्री पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर हैं। खबरों के मुताबिक, ठाकरे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाए, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस उनके साथ एकमत नहीं हैं, जिसे इस कार्यक्रम में शामिल न होने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। हालांकि, स्थिति साफ करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी प्रमुख नाराज नहीं हैं और दूर रहने के उनके फैसले के पीछे कोई राजनीति नहीं है। राउत ने कहा कि उनके कार्यक्रम और बैठकें पहले से निर्धारित थीं, और इसलिए वह सांगली समारोह के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस बीच, उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति स्पष्ट रही और इस अवसर पर शिव सेना (यूबीटी) का कोई अन्य नेता मौजूद नहीं था। इससे पहले दिन में गांधी ने कांग्रेस के दिवंगत नांदेड सांसद वसंत चव्हाण के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उसके बाद, पूर्व कांग्रेस प्रमुख सांगली आए, जहां उन्होंने वांगी में पतंगराव कदम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। गांधी ने दिवंगत नेता को समर्पित एक संग्रहालय का भी दौरा किया। उन्होंने सांगली में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित किया।



अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। दिल्ली एक्सप्रेस मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सुकान्त और जस्टिस भुईया ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगले हफ्ते तक शायद इस पर फैसला आ सकता है। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलीलें पेश करनी शुरू कीं और उच्चतम न्यायालय को बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं। जमानत का अनुरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके भागने का जोखिम नहीं है।



सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को करीब दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया, ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद 'बीमा गिरफ्तारी' की गई। अभिषेक सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया, अधीनस्थ अदालत ने गिरफ्तारी का एकपक्षीय आदेश पारित किया। केजरीवाल मामले की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि मामले में सिसोदिया और कविता समेत हर

संभावित सह-आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने उच्चतम न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की याचिका का सीबीआई की ओर से विरोध किया और कहा कि उन्हें जमानत के लिए अधीनस्थ अदालत जाना चाहिए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस इसलिए जारी नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोपपत्र की प्रति संलग्न नहीं की है, उनकी जमानत याचिका चीजों को छिपाने के आधार पर खारिज की जानी चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है, तो इससे दिल्ली उच्च न्यायालय का मनोबल गिरेगा।

रविंदर रैना ने दाखिल किया अपना नामांकन

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख और नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रविंदर रैना ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो भी किया। रविंदर रैना ने कहा कि पूरे जम्मू-कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त लहर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब होने के बावजूद भी नौशेरा के भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए एकत्र हुए और इस रोड शो को अंजाम दिया।

रैना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जब यहां मतदान होगा तो भारी बहुमत पर भाजपा की सरकार बनेगी। नौशेरा के नेतृत्व में बीजेपी जम्मू-कश्मीर में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनके गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू-कश्मीर के अत्यंत सम्मानित महाराजाओं का अपमान किया है। जम्मू-कश्मीर के लोग निश्चित रूप से कांग्रेस, राहुल गांधी और उनके गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में चुनाव होने हैं।

इटली का चश्मा हटाएं, सब कुछ साफ दिखने लगेगा, राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बीजेपी प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पर कड़ा प्रहार करते हुए तरुण चुघ ने कहा कि राहुल गांधी यहां एक पर्यटक के रूप में आए हैं। वह जम्मू-कश्मीर के विकास का विरोध करते हैं। 70 साल तक उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इटली का चश्मा लगा रखा है, और वह एक पर्यटक के रूप में जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वह राज्यपाल को बाहरी कहते हैं। अपना हमला रखते हुए तरुण चुघ ने कहा कि आपको सबसे पहले इटली का चश्मा हटाना चाहिए, फिर उन्हें सब कुछ साफ-साफ दिखाई देने लगेगा। इससे पहले अनुराग ठाकरे ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री जो साफ कहे कि विधानसभा चुनाव होते ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद पत्थरबाजी, आतंकवाद और अलगाववाद को घटनाएं खत्म हो गई हैं। भाजपा यहां शांति समृद्धि और प्रगति लेकर आई। यहां के लोग खुश हैं।

स्टील प्रमुख समाचार

बीसीसीआई के नए सचिव का चुनाव अभी नहीं!

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को 93वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) यहां 29 सितंबर को होगी लेकिन इस बैठक में बोर्ड के नए सचिव का चुनाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि एजीएम शहर के बाहरी इलाके में अत्याधुनिक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के उद्घाटन के दौरान ही होगी क्योंकि बोर्ड के सभी सदस्य शहर में मौजूद रहेंगे। दो दशक से अधिक समय पहले अस्तित्व में आने के बाद से एनसीए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसर से संचालित हो रहा है।



एजीएम में बीसीसीआई के नए सचिव का चुनाव नहीं होगा लेकिन इस बैठक में चुनाव के लिए विशेष आम बैठक (एसजीएम) की तारीख तय की जा सकती है। निवर्तमान सचिव जय शाह के सर्वसम्मति से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का चेयरमैन चुने जाने के बाद नए सचिव की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है।

शाह हालांकि एजीएम में बीसीसीआई सचिव की अपनी मौजूदगी भूमिका नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें आईसीसी चेयरमैन का प्रभार एक दिसंबर से संभालना है। सभी राज्य संघों को भेजे गए बैठक के 18 सूत्री एजेंडे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आईसीसी बैठकों में बीसीसीआई के प्रतिनिधि की नियुक्ति है क्योंकि शाह अब उस भूमिका के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। आईसीसी में बोर्ड के प्रतिनिधि के लिए बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष रोजर बिन्नी के नाम पर चर्चा हो सकती है या यह पद नए सचिव को मिल सकता है। लेकिन 69 वर्षीय बिन्नी के लिए उम्र उनके पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रशासन में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र 70 वर्ष है। इन दो महत्वपूर्ण मामलों के अलावा एजीएम में आईपीएल की संचालन परिषद में आम सभा के दो और भारतीय क्रिकेटर्स संघ (आईसीए) के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।

निफ्टी में दूसरे दिन भी गिरावट संसेक्स लाल निशान में बंद

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में आज आंठों और रियल्टी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। एशियाई शेयर बाजार आज नरम रहे। 5 सितंबर को निफ्टी-50 लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। 50 शेयरों वाला एनएसई आई बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 53.60 अंक या 0.21% की गिरावट के साथ 25,145.10 के लेवल पर बंद हुए। तो वहीं आज एफएंडपी बीएसई संसेक्स में भी लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। 30 शेयरों वाला संसेक्स आज 0.18% या 151.48 अंकों की गिरावट के साथ 82,201.16 के लेवल पर बंद हुआ। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान, निफ्टी 50 बढ़त बनाते हुए 25,275.45 के लेवल पर और संसेक्स 82,617.49 के हाई लेवल पर गए थे। संसेक्स के 30 शेयरों में से कुल 10 शेयर ही आज हरे निशान में बंद हुए, जबकि निफ्टी-50 के 17 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

लगातार बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था : शक्तिकांत दास

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी चालक गति पकड़ रहे हैं और देश सतत वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एफआईबीएसपी 2024 के उद्घाटन भाषण में गवर्नर ने कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा बाजारों में व्यापक पर बदलाव हो रहे हैं और देश इन बदलाव के लिए तैयार है। दास ने कहा, "उत्त अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमारे देश की यात्रा को कई कारकों के अनूठे मिश्रण से बल मिल रहा है। इन कारकों में युवा व ऊर्जस्वी आबादी, जुलारू व विविध अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और उद्यमशीलता व नवाचार की समृद्ध परंपरा शामिल हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की वृद्धि गाथा अक्षुण्ण है और बैंकों का बहीखाता मजबूत है। दास ने निजी क्षेत्र से व्यापक स्तर पर निवेश बढ़ाने का आग्रह किया।

वाहन कंपनियों की अगस्त में 5 प्रतिशत घटी कारों की बिक्री

नई दिल्ली। देश में गाड़ियों की बिक्री में कमी से वाहन कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। भारत में यात्री वाहन की रिटेल बिक्री में अगस्त में सालाना आधार पर पांच प्रतिशत घट गई। उद्योग संगठन फाडा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फाडा की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में कुल 309,053 यात्री वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि अगस्त 2023 में यह संख्या 323,720 थी। बता दें कि ग्राहक खरीद में देरी समेत उपभोक्ताओं के खराब सेंटीमेंट और लगातार भारी बारिश के कारण देश में कारों की बिक्री अगस्त में घटी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बयान में कहा, "त्यौहारी मौसम के बावजूद बाजार पर काफी दबाव बना हुआ है, वाहन अब 70-75 दिन तक गोदाम में रखे रहते हैं, और 'इन्वेंट्री' कुल 7.8 लाख वाहनों की है, जिसका मूल्य 77,800 करोड़ रुपये है।"

त्यौहार सीजन से पहले जनता को महंगाई का झटका

नई दिल्ली। देश में गणेश चतुर्थी से त्यौहारों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मंडियों में सब्जियों के अब फलों के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इन दिनों सबसे ज्यादा रेट केले के बढ़े हुए हैं। कई राज्यों में केले दाम पहुंचे 100 से 120 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। राजधानी में केले के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सेब के दाम में भी 20 फीसदी तक रेट बढ़ गए हैं। व्यापारियों का मानना है कि, त्यौहारी सीजन में फल की मांग बढ़ जाती है। इससे कीमतों में तेजी आ जाती है। आने वाले दिनों में फलों की कीमत में और इजाफा हो सकता है। दरअसल, कई राज्यों में फलों के दाम डिमांड और मांग में अंतर आने की वजह से बढ़ रहे हैं। बारिश और खराब मौसम भी दाम बढ़ने की एक वजह बताई जा रही है।

प्रह्लाद सबनानी

अमेरिका विश्व के लगभग समस्त देशों पर अपनी चौधराहत सफलतापूर्वक लागू करता रहा है। पूरे विश्व में, एक तरह से लगभग समस्त क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की नीतियों को प्रभावित करने में अमेरिका सफल रहा है एवं इस प्रकार अपनी प्रसारवादी नीतियों को भी लागू करता रहा है। परंतु, हाल ही के वर्षों में अमेरिका की आंतरिक स्थिति, लगभग समस्त क्षेत्रों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आदि, में लगातार बिगड़ती जा रही है। अमेरिका सहित विकसित देशों की, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में, आंतरिक स्थिति को देखते हुए अब तो पश्चिमी सभ्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं।

अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में आर्थिक विपन्नता एवं परिवार तथा समाज के

खंड खंड होने के बाद पश्चिमी सभ्यता को पतित सभ्यता कहा जाने लगा है और इसे अब अमेरिकी स्वप्न के अंत की शुरुआत भी माना जाने लगा है।

अमेरिका में तो राष्ट्रीय ऋण 35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। इसका आशय यह है कि आय की तुलना में ऋण अधिक ले लिया गया है। अमेरिकी वित्त व्यवस्था पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि अमेरिकी सरकार को अपने सामान्य खर्चों को चलाने के लिए भी बाजार से और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है और इस उद्देश्य से प्रति वर्ष अमेरिकी संसद में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पहुंचना होता है। यह स्थिति है विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली देश अमेरिका की।



वर्ष 1776 में जब पूंजीवाद के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने अपनी कृति द वेल्थ आफ नेशनस नामक किताब जारी की थी उस समय पूंजीवाद अपने शैशवावस्था में ही था। उनका महत्वपूर्ण मुख्य सिद्धांत था कि व्यवसायी, जो अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय को बहुत ही कुशलता के साथ चलाना चाहते हैं। इस तरह ये व्यवसायी न केवल अपने आप को धनाढ्य बनाएंगे बल्कि वह देश इन धनाढयों के संसाधनों को जोड़कर स्वयं भी एक धनी देश बन जाएगा। पूरी 19वीं शताब्दी

एवं 20वीं शताब्दी में अमेरिका इसी सिद्धांत पर कार्य करता रहा है एवं अपने देश में धनाढयों की संख्या में अपार वृद्धि करता रहा है। इससे अमेरिकी नागरिकों में व्यक्तिवाद पनपा एवं वे परिवार एवं समाज के भले को भूलकर केवल अपने चारों में ही सोचने लगे एवं अपने व्यापार को पूरे विश्व में फैलाने लगे। इससे अमेरिका में गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही।

अमेरिका की 1940 के दशक में पूरे विश्व के विनिर्माण क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो गई थी, परंतु अब यह घटक 17 प्रतिशत से भी कम हो गई है। कई उद्योगों के मामले में उत्पादन का जो एकाधिकार अमेरिका के पास होता था वह एकाधिकार अब अन्य देशों के पास चला गया है। अमेरिकी कम्पनियों ने कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्चों की पूरी लागत स्वयं वहन

करना प्रारम्भ किया था। अमेरिका में श्रम लागत भी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, अन्य देशों में श्रमिक, अमेरिकी श्रम लागत की तुलना में, आधी से भी कम राशि में ही काम करने को तैयार हो रहे थे। इस बीच अमेरिकी सरकार ने आय कर की दरें भी बढ़ाकर 35 प्रतिशत से अधिक कर दी थीं। जबकि अन्य देशों में आय कर की दरें 20/25 प्रतिशत थीं। इससे अमेरिका में विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ने लगी। अतः धीरे धीरे अमेरिका में विनिर्माण इकाइयां बंद होने लगीं। वर्ष 1979 में अमेरिका में 20 प्रतिशत श्रमिक विनिर्माण इकाइयां बंद कार्यरत थे अब यह संख्या घटकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गई है। अमेरिका में 2 करोड़ कर्मचारी विनिर्माण इकाइयां में कार्य कर रहे थे जो घटकर 1 करोड़ 20 लाख हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को जबरदस्त रिस्पांस: विजया



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और सदस्यता अभियान की छत्तीसगढ़ प्रभारी विजया राहटकर ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान की प्रगति की सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक की हुई कार्यशालाओं के बाद इस अभियान में जुटे पार्टी के 3.65 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों, क्षेत्रों तक पहुंचकर सदस्यता के अभियान को गति देंगे और जन-मन को जोड़कर काम कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में सदस्यता के लक्ष्य को पार करेंगे। सुश्री राहटकर ने कहा कि इस अभियान को हम सर्वस्पर्शी व

सर्वसमावेशक बनाकर भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखकर हर बूथ के सभी समाज, वर्ग को हम स्पर्श करेंगे।

भाजपा सदस्यता अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा बैठक लेने राजधानी पहुंची सुश्री राहटकर ने गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सदस्यता नवीनीकरण का अभियान पूरे देश में शुरू हो चुका है। 2014 व 2019 के सदस्यता अभियान की चर्चा करते हुए सुश्री राहटकर ने कहा कि कार्यकर्ताओं व जनता जनार्दन के सतत सम्पर्क के कारण छत्तीसगढ़ में इस अभियान को बहुत

अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फोन नं. 8800002024 पर मिस्ट कॉल करके, वयूआर कोड स्कैन करके, नमो एप और भाजपा की वेबसाइट पर जाकर भाजपा की सदस्यता ली जा सकती है। सुश्री राहटकर ने कहा कि राष्ट्रनिर्माण की भावना और 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने देश के हर नागरिक को जोड़ना इस अभियान का उद्देश्य है। इसी के साथ भाजपा की विचारधारा और भाजपानित सरकारों की जनकल्याणकारी उपलब्धियों की चर्चा करके हम सबको पार्टी के साथ जोड़ेंगे। सुश्री राहटकर ने कहा कि भाजपा का सदस्य या हितैषी हमारे लिए सिर्फ एक अंक नहीं है,

अपितु वह हमारी विचारधारा का वाहक और कार्य संस्कृति का पोषक भी है।

भाजपा सदस्यता अभियान की प्रदेश प्रभारी सुश्री राहटकर ने कहा कि पार्टी के इस सदस्यता अभियान में सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ, प्राधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता सहयोग करेंगे और सदस्यता के लक्ष्य को अर्जित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के बाद प्रदेश, जिला और मंडल इकाइयों में सदस्यता अभियान की शुरुआत के बाद अब कल 6 सितंबर से शक्ति केंद्रों पर अभियान शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार 11 सितंबर को संसद सदस्य, 12 सितंबर को विधायक-विधायक प्रत्याशी, 13 सितंबर को नगरीय निकाय के सभी जनप्रतिनिधि और 14 सितंबर को सदस्यता अभियान का उद्देश्य है। इसी के साथ भाजपा की विचारधारा और भाजपानित सरकारों की जनकल्याणकारी उपलब्धियों की चर्चा करके हम सबको पार्टी के साथ जोड़ेंगे। सुश्री राहटकर ने कहा कि भाजपा का सदस्य या हितैषी हमारे लिए सिर्फ एक अंक नहीं है,

को सफल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह अभियान बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुआ है और अपने लक्ष्य को पार करने में सफल रहेगा। सुश्री राहटकर ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता संगठन व सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मिस्ट कॉल के जरिए सदस्यता लेने वाले कार्यकर्ताओं को भी हम कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भाजपा की थाती हैं और पार्टी अपने सभी नए-पुराने कार्यकर्ताओं की पूरी चिंता करती है।

इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सक्ती, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव, संभाग प्रभारी रजनीश सिंह, अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।

शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मजाक बनाने वाले भूपेश के बयान पर राजेश का हमला

बघेल हिंदू भावनाओं को लगातार आहत कर रहे हैं : राजेश मूणत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, विधायक व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विल्व पत्र और भगवान शंकर को जल चढ़ाने की आस्था का संरेआम उपहास उड़ाने के लिए कड़ी आलोचना की है। श्री मूणत ने कहा कि इससे बघेल और कांग्रेस का हिन्दू और



विल्व पत्र चढ़ाने का भद्दे ढंग से उपहास उड़ाने देखे-सुने जा रहे हैं, का हवाला देकर कहा कि बघेल के पिता का पूरा जीवन हिन्दुओं के देवी-देवताओं और सनातन संस्कृति पर अनर्गल टिप्पणियाँ करने में बीत गया और मुख्यमंत्री रहते हुए भी बघेल इन टिप्पणियों पर मौन साधे बैठे रहे।

सनातन विरोधी चरित्र बेनकाब हो गया है। हिन्दू विरोधी मानसिकता बघेल को अपने पिता से ही विरासत में मिली है। राजनीतिक लाभ बटोरने के लिए राम, सीता और माता कौशल्या के नाम पर पाँच साल तक पाखंड का प्रदर्शन करते रहे बघेल का वह हिन्दू व सनातन विरोधी असली राजनीतिक चरित्र जगजाहिर हो गया है, जिसकी पोषक कांग्रेस शुरू से रही है और अब कांग्रेस से जुड़े इंडी गठबंधन के नेता भी इसी भाषा में देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था और भावनाओं का संरेआम उपहास उड़ाने का दुस्साहस कर रहे हैं। भूपेश बघेल के बयान से शिवभक्तों में भारी आक्रोश है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री मूणत ने एक कार्यक्रम के वायरल वीडियो, जिसमें बघेल भगवान शंकर को अर्पित किए जाने वाले जल व

आज खुद भूपेश बघेल ने भगवान शंकर, जल व विल्व पत्र का खुलेआम मजाक उड़ाकर अपने डीएनए का परिचय दे दिया है। श्री मूणत ने कहा कि यही हिन्दू और सनातन विरोधी डीएनए कांग्रेस व इंडी गठबंधन का भी गांठे-बगांठे सामने आता रहा है। सनातन धर्म को लेकर द्रुपद सरकार के एक मंत्री ने भी शर्मनाक टिप्पणी की थी और कांग्रेस अध्यक्ष महिष्कार्जुन खड्गे के बेटे ने उसका सार्वजनिक रूप से समर्थन करके कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र को बेनकाब कर दिया था। श्री मूणत ने कहा कि तुष्टीकरण का एजेंडा चलाकर भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल में प्रदेश का वितावरण बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और अब अपने उसी एजेंडे पर खुलेआम सामने आ गए हैं।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकारें प्रतिबद्ध : विजया राहटकर

महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में अनेक महिलाओं ने मिस्ट कॉल के जरिए ली भाजपा की सदस्यता

रायपुर। महिला स्व सहायता समूह के तत्वावधान में गुरुवार को राजधानी के वृंदावन हाल में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भाजपा की मातृ-शक्ति ने भाजपा पर भरोसा करते हुए प्रदेश में फिर से भाजपा

की सरकार बनाई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश की विष्णु देव सरकार ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित करके महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकारें प्रतिबद्ध हैं। सुश्री राहटकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके आत्म-सम्मान की

चिंता भाजपा की प्राथमिकता है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुश्री राहटकर ने तीजा महोत्सव कार्यक्रम में आई महिलाओं को 8800002024 नंबर पर मिस्ट कॉल करवाकर उन्हें भाजपा का सदस्य बनाया। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाजपा की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी काफी संख्या में उपस्थित रहीं। प्रदेश भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव, सांसद रूपकुमारी चौधरी, अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, चन्नी वर्मा, शहर जिला भाजपा महामंत्री सत्यम दुवा, अमर बंसल, अकबर अली, विभा राव आदि ने इस कार्यक्रम में शिरकत की।

प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेस करेगी सीएम हाउस का घेराव, भाजपा महामंत्री संजय बोले- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

रायपुर. छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर सियासी पारा हाई है। महिला कांग्रेस ने प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर 10 सितंबर को सीएम निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने इस घेराव को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस पहले अपनी संख्या को बता दे, जिनके पास न लोग हैं, न टीम है। उनके घेराव का कोई औचित्य ही नहीं है। कांग्रेस अपनी असफलता को छुपाने के लिए जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। बता दें, महिला कांग्रेस ने आज राजधानी के राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर महिलाओं की सुरक्षा मामले में राज्य की कानून व्यवस्था को लचर बताते हुए भाजपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।



महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि प्रदेश में आये दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मूकदर्पक बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 महाने की सरकार में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आये हैं। महिलाओं के खिलाफ 3 हजार से ज्यादा

आपराधिक घटना हुई हैं। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं इसलिए अपराधियों का हौसला बुलंद है। आज एक 4 साल की छोटी भिलाई की बच्ची हो या फिर रायपुर नया बस स्टैंड में एक 50 साल की महिला हो सब के साथ दुष्कर्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि जशपुर, केशकाल, पखांजूर दुर्ग, राजधानी रायपुर और रायगढ़, सक्ती, अंबिकापुर में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन आरोपी को

बाजपाई छत्तीसगढ़ में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी पर मौन है। महिलाओं के अधिकार के लिये महिलाओं के सुरक्षा के लिये महिला कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी और 10 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा कोई अपराध और भ्रष्टाचार, घोटाला नहीं जो पिछले पांच सालों में न हुआ हो। कांग्रेस के लिए एक कहावत लम्बा रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दीपक बैज और महिला कांग्रेस को प्रदर्शनकारी महिलाओं की संख्या बतानी चाहिए। कांग्रेस अपनी असफलता को छुपाने के लिए जान-बूझकर ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है।

दुर्ग एसपी को हटाए बिना जांच और न्याय की उम्मीद नहीं

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि दुर्ग एसपी को हटाए बिना डीपीएस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद नहीं है। डीपीएस मामले में लीपापोती करने के लिए पास्को एक्ट के मामले में भी एफआईआर दर्ज नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी डीपीएस मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जब आंदोलन किया, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन की, तब कहीं जाकर कांग्रेस के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब डीपीएस स्कूल के अन्य पालकों के द्वारा स्कूल के सामने मामले में कार्यवाही के लिये 2 अगस्त को प्रदर्शन किया गया। तब पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। 3 अगस्त को दुर्ग के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बयान दिया कि बच्ची के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अखबारों में छपी खबर गलत और भ्रामक है। जब एक न्यूज पोर्टल ने इस मामले की पूरी खबर लगातार छपा तो पुलिस अधीक्षक ने पालकों के वाट्सअप ग्रुप में न्यूज पोर्टल की खबर पर सवाल खड़ा करते हुये धमकाया कि न्यूज पोर्टल पर भी कार्यवाही हो सकती है।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के डबल इंजन के सरकार में लगातार खासकर त्यौहार के समय ट्रेनें रद्द करना एक परंपरा हो गई है। साल भर से महिलाएं तीजा पर्व के इंतजार करती हैं, तीजा त्यौहार में महिलाएं अपने मायके जाती हैं। भाजपा सरकार में तीजा के समय फिर से 15 ट्रेनें रद्द कर दिये गये हैं। साथ ही ट्रेनों का रूट भी बदले गये हैं जिनके कारण महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यमवर्गीय परिवार के लिए आवागमन करने के सबसे अच्छा सस्ता साधन रेल होता है। तीजा पर्व के हफ्तों भर पहले आने जाने का टिकट का बुकिंग करना लेते हैं। लेकिन भाजपा सरकार के फेलवर नीति के कारण तीजा त्यौहार में रेल रद्द कर दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बातों को दरकिनार कर दिया गया। पहली बार भाजपा लोकसभा सांसद ने रेल से प्रशांत परेशानी का जिक्र संसद में किये थे लेकिन अपने पार्टी के सांसद के बातों को ही अनसुना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई से सभी वर्ग प्रसन्न हैं। प्राइवेट गाड़ी करके आना-जाना मध्यमवर्गीय परिवार के लिये एक सपना है क्योंकि बेलगाम महंगाई से सिर्फ ट्रेन ही साधन होता है।

तीजा त्यौहार में रेल रद्द होने से महिलाएं परेशान

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के डबल इंजन के सरकार में लगातार खासकर त्यौहार के समय ट्रेनें रद्द करना एक परंपरा हो गई है। साल भर से महिलाएं तीजा पर्व के इंतजार करती हैं, तीजा त्यौहार में महिलाएं अपने मायके जाती हैं। भाजपा सरकार में तीजा के समय फिर से 15 ट्रेनें रद्द कर दिये गये हैं। साथ ही ट्रेनों का रूट भी बदले गये हैं जिनके कारण महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यमवर्गीय परिवार के लिए आवागमन करने के सबसे अच्छा सस्ता साधन रेल होता है। तीजा पर्व के हफ्तों भर पहले आने जाने का टिकट का बुकिंग करना लेते हैं। लेकिन भाजपा सरकार के फेलवर नीति के कारण तीजा त्यौहार में रेल रद्द कर दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बातों को दरकिनार कर दिया गया। पहली बार भाजपा लोकसभा सांसद ने रेल से प्रशांत परेशानी का जिक्र संसद में किये थे लेकिन अपने पार्टी के सांसद के बातों को ही अनसुना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई से सभी वर्ग प्रसन्न हैं। प्राइवेट गाड़ी करके आना-जाना मध्यमवर्गीय परिवार के लिये एक सपना है क्योंकि बेलगाम महंगाई से सिर्फ ट्रेन ही साधन होता है।

होटल में शराब बेचते पकड़े दोनो आरोपी जेल गये

रायपुर। बीते कल बुधवार को मंदिर हसीद थाना अमला ने मुखबिर् की सूचना पर ग्राम रीवा में दबिश दे दो अवैध शराब विक्रेताओं को शराब बेचते रंगे हाथ पकड़ा। ग्राम के ही 55 वर्षीय कलीराम साहू को सहायक उपनिरीक्षक चंद्रहास वर्मा के साथ गश्ती में निकले आरक्षकद्वय अशोक प्रधान व निहाली साहू की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास 42 पीव्वा शराब के साथ जहां पकड़ा वहीं मानिक राम साहू को अपने गांव के भाठपारा स्थित होटल में 38 पीव्वा शराब के साथ गश्ती प्रधान ?आरक्षक अमित मिश्रा के साथ गये आरक्षक खिलेश्वर साहू की टीम ने दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी सचिन सिंह के अगुवाई में निजात अभियान के तहत की जा रही कार्यवाही के दौरान दोनो एक ही दिन में सपड़ में आये। गिरफ्तार दोनो आरोपियों को अदालती आदेश पर जेल दाखिल करा दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि कुछ दिन पूर्व ही ग्राम टेकारी के दो अवैध शराब विक्रेता अंकलेश्वर वर्मा व मिथिलेश वर्मा को शराब लाते रास्ते में ही पकड़ कर न्यायालयीन आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद में शिक्षक दिवस मना

रायपुर। भारत के पुर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद सप्ते शाला परिसर में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ रायपुर कॉम्पोर्नलेशन की डिस्ट्रिक्ट ई.एस. ओ. डा. मंजूषा वैशंपायन, अध्यक्ष वर्षा सिंघानिया, पूर्व अध्यक्ष अंजली खेर की अध्यक्षता में डा. श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और उनके जीवन की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए परिषद के संयुक्त सचिव प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा जैन संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम ने अपने उद्बोधन में उन्हें याद करते हुए शिक्षक दिवस को सार्थक करने हेतु अपील की। इस अवसर पर परिषद में कार्यरत सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह माना कैम्प, मानसिक दिव्यांग बाल गृह (बालक) माना कैम्प, बाल जीवन ज्योति एवम अनुसंधान केन्द्र मानसिक दिव्यांग गृह (बालिका) नगरीय दास मंदिर परिसर पुरानी बस्ती, बालिका गृह कोडगांव में भी शिक्षक दिवस मनाया गया इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

हेड मास्टर ने छात्रों को नारियल लाने भेजा, एक छात्र की मौत

दुर्ग। शिक्षक दिवस समारोह के लिए हेड मास्टर ने अपनी बाइक देकर सातवीं कक्षा के बच्चों को नारियल लाने भेज दिया। रास्ते में बच्चे हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया है। घटना के बाद बीईओ ने हेड मास्टर को स्पेड कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीईओ को पत्र लिखा है। घटना पाटन क्षेत्र के ग्राम कोही की है। शिक्षक दिवस के मौके पर मिडिल स्कूल के हेड मास्टर ने अपनी बाइक देकर सातवीं कक्षा के दो बच्चों को नारियल लाने भेज दिया, लेकिन गांव से थोड़ी दूर पर बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। घायल दोनों बच्चों को शासकीय अस्पताल ले जाया गया। इनमें छात्र वीमेश कुमार साहू की मौत हो गई, वहीं दूसरे छात्र भूपेश तिवारी को गम्भीर चोट आई है, जिसका दुर्ग जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हेड मास्टर संतोष महिलांग को बीईओ ने निर्लिंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीईओ को पत्र लिखा है।



प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़/राजधानी

नियद नेल्लानार योजना के कार्यों को गंभीरता पूर्वक पूर्ण करें

अपराध और नशामुक्त कर छत्तीसगढ़ को विकसित एवं समृद्ध बनाने में योगदान दें: वर्मा

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नारायणपुर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से कोई भी महिला हितग्राही वंचित न रहे। यह योजना सतत प्रक्रियानी है। किसी कन्या की विवाह होने पर उनके आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए ऑनलाईन पंजीयन कराए। इसी तरह अपराध

प्रधानमंत्री आवास को शीघ्र प्रारंभ कराए ताकि लोगों के जीवन स्तर प्रकाश सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग और जनपद विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्यमन्त्री के अनुरूप हितग्राहियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नलजल, प्रधानमंत्री आवास मिल सके। जिससे क्षेत्र के विकास में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि अबुल्लाडू क्षेत्र के लोगों के हाथों में बंदूक नहीं बल्कि कलम होना चाहिए, जिससे उनका भविष्य संवरेगा और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें। राजस्व विभाग के कार्यों की पंचायत विभाग के कार्यों का समीक्षा कर हितग्राही मूलक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने कहा। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के मंशानुसार अबुल्लाडू क्षेत्र के

समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि वृत्ति सुधार और सीमांकन के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। नियद नेल्लानार के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के दुर्गम क्षेत्र मोहंदा, इरकभट्टी, मसपुर और कस्तूरमेटा में कार्य प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री ब्रिपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, डीएफओ श्री सच्चिदानंदन के., अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र बहादुर पंचभाई सहित जिला स्त्रीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर में नवनिर्मित विपश्यना ध्यान केन्द्र धम्मकुटी में पहला दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर का आयोजन 22 सितंबर से किया जा रहा है। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक आयोजित दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का संचालन रायपुर के सहायक आचार्य श्री गंगाराम प्रजापति करेंगे। छत्तीसगढ़ विपश्यना ट्रस्ट के आचार्य श्री सीताराम साहू ने बताया कि परंपरा अनुसार आवासीय शिविर में विपश्यना ध्यान की शिक्षा नि:शुल्क ही दी जाती है तथा भोजन एवं आवासीय व्यवस्था कृतज्ञ साधकों के स्वैच्छिक दान से होता है। 20 वर्ष से अधिक उम्र के इच्छुक व्यक्ति शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। धम्मकुटी में 2024 की अवधि में 12 सितंबर से 3 अक्टूबर के बाद 23 से 24 अक्टूबर, 7 से 18 नवंबर तथा 8 से 19 दिसंबर तक दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर आयोजित है। केन्द्री के पास सिंगारभाठा में निर्मित यह ध्यान केन्द्र दुर्ग और बिलासपुर के बाद प्रदेश का तीसरा विपश्यना ध्यान केन्द्र

रायपुर में धम्मकुटी विपश्यना केन्द्र में पहला दस दिवसीय शिविर 22 सितंबर से

रायपुर। रायपुर में नवनिर्मित विपश्यना ध्यान केन्द्र धम्मकुटी में पहला दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर का आयोजन 22 सितंबर से किया जा रहा है। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक आयोजित दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का संचालन रायपुर के सहायक आचार्य श्री गंगाराम प्रजापति करेंगे। छत्तीसगढ़ विपश्यना ट्रस्ट के आचार्य श्री सीताराम साहू ने बताया कि परंपरा अनुसार आवासीय शिविर में विपश्यना ध्यान की शिक्षा नि:शुल्क ही दी जाती है तथा भोजन एवं आवासीय व्यवस्था कृतज्ञ साधकों के स्वैच्छिक दान से होता है। 20 वर्ष से अधिक उम्र के इच्छुक व्यक्ति शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। धम्मकुटी में 2024 की अवधि में 12 सितंबर से 3 अक्टूबर के बाद 23 से 24 अक्टूबर, 7 से 18 नवंबर तथा 8 से 19 दिसंबर तक दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर आयोजित है। केन्द्री के पास सिंगारभाठा में निर्मित यह ध्यान केन्द्र दुर्ग और बिलासपुर के बाद प्रदेश का तीसरा विपश्यना ध्यान केन्द्र

पश्यना, दैनिक जीवन के तनाव और कठिनाइयों को शांत एवं संतुलित तरीका से सामना करने के लिये यह स्व-सजगता की व्यावहारिक विधि है। जीवन-जीने की इस कला से मानसिक विकार दूर होते हैं। आज के तनाव भरे जीवन में युवाओं को विशेषकर लाभ मिला है। आनापान के माध्यम से व्यक्ति अपने श्वास को देखते हुए अपने अंदर हो रहे बदलावों को जानता है। नियमित अभ्यास के बाद सबसे पहले व्यक्ति को बेचैनी, चबराहट, भय जैसी मानसिक परेशानी के बचाव होता है।